● वर्ष : 17 ● अंक : 101 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित

गुरुवार 29 जनवरी 2026

लैंडिंग के दौरान अजीत पवार का विमान क्रैश, उपमुख्यमंत्री पवार सहित 6 की मौत

एजेंसी। मुंबई

महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई। हादसा बारामती के हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान हुआ। दुर्घटना के बाद घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त और जला हुआ दिखाई दिया। इस हादसे में कुल पांच लोगों की मृत्यु हुई है। इनमें अजित पवार के साथ उनके अंगरक्षक विदीप जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट कैप्टन सुमित कपूर तथा कैप्टन शांभवी पाठक शामिल हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बताया कि विमान लियरजेट 45 (वीटी-एसएसके) आज सुबह बारामती एयरपोर्ट पर क्रैश लैंड हो गया। विमान में पांच लोग सवार थे, जिनमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्रीअजीत पवार के साथ दो और लोग (एक पीएसओ और एक अटेंडेंट) और 2 क्रू मेंबर शामिल थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि जिला परिषद चुनावों के मद्देनजर अजित पवार की बुधवार को बारामती में चार जनसभाएं प्रस्तावित थीं। इन्हीं कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए वे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। विमान जब बारामती में उतरने की प्रक्रिया में था, तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अजित पवार जिस विमान से यात्रा कर रहे थे वह बॉम्बार्डियर कंपनी का लियरजेट-45 श्रेणी का था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विमान पहले नीचे की ओर आता दिखा, फिर अचानक अनियंत्रित होकर जमीन से टकरा गया, जिसके बाद तेज विस्फोट हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जमीन से जुड़े जननेता, मेरे मित्र और सहयोगी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन की खबर से मन व्यथित है। मैंने अपना एक दमदार और दिलदार मित्र खो दिया है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। यह घटना महाराष्ट्र के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। मैं अजितदादा इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार के दुःख में हम सब साथ है। अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में हुआ था। राजनीति में 'दादा' के नाम से लोकप्रिय अजित पवार अपनी स्पष्टवादिता और मजबूत प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1982 में सहकारी क्षेत्र से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की।

प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने महाराष्ट्र के अजित पवार के निधन पर जताया शोक

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के बारामती में आज सुबह हुए विमान हादसे में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर उन्हें आमजन का नेता बताया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अजित पवार के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि बारामती में हुए इस विमान हादसे से वे अत्यंत दुखी हैं। हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं और इस गहन दुख की घड़ी में उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री ने अजित पवार को आमजन का नेता बताते हुए कहा कि उनका जमीनी स्तर से गहरा जुड़ाव था और वह महाराष्ट्र की जनता की सेवा में सदैव अग्रणी रहे।

राष्ट्रपति, गडकरी, खरगे, राहुल गांधी ने अजित पवार के निधन पर जताया शोक

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के बारामती में आज सुबह हुए विमान हादसे में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, केंद्रीयमंत्री नितिन गडकरी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है। नेताओं ने इसे महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि बारामती में हुई विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अजित पवार का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है और महाराष्ट्र के विकास, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

यूजीसी के नए नियम से बढ़ता असंतोष

देशभर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शिक्षा संस्थानों के लिए जो नए नियम लागू किए हैं, उसको लेकर देश भर में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। उच्च शिक्षा व्यवस्था में विश्वास, विचारधारा, सरकार की उपेक्षा जातिगत एवं धार्मिक भेदभाव के कारण पिछले एक दशक से उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र-छात्राओं के बीच में भारी रोष देखने को मिल रहा था। जो नए नियम लागू किए गए हैं उसके बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले सभी वर्ग के छात्रों में उसकी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक गंभीर सवाल बन चुका है। 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026' के नाम से 13 जनवरी को जो नई व्यवस्था अधिसूचित की गई है, उसका उद्देश्य भले ही कैंपस में भेदभाव खत्म करना बताया जा रहा हो, लेकिन इसके क्रियान्वयन और दायरे को लेकर स्वर्ण वर्ग और सामान्य वर्ग की आशंकाएं गहरा गई हैं।

ब्राह्मण वर्ग द्वारा जिस तरह का विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है, उसके बाद दिल्ली स्थित उच्च शिक्षा अनुदान आयोग (यूजीसी) के मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई, देश के कई राज्यों में प्रदर्शन, इस्तीफे, प्रतीकात्मक विरोध, चूड़ियां भेजना और सोशल मीडिया पर पक्ष और विपक्ष को लेकर आलोचना और समर्थन यह सभी विरोध के संकेत हैं। इसकी क्रिया और प्रतिक्रिया सीमित दायरे तक नहीं है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक वरिष्ठ अधिकारी का इस्तीफा और करणी सेना द्वारा भारत बंद की चेतावनी, यह दर्शाती है, मामला अब शिक्षा नीति से आगे सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है। नए नियमों के तहत सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समान अवसर केंद्र गठित किए जाएंगे। इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। विशेष शिकायत समितियां, 24 घंटे की हेल्पलाइन और निगरानी तंत्र का प्रावधान किया गया है।

इनका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों से जुड़ी शिकायतों के तुरंत निराकरण के लिए होगा। सरकार और यूजीसी का तर्क है, कि यह कदम इसलिए जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में भारी वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा संस्थानों में उच्च वर्ग के लोगों द्वारा एसटी, एससी और अन्य वर्ग के छात्रों को प्रताड़ित किए जाने की घटनाएं बढ़ रही थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में मजबूत कानून बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं उनमें सामान्य श्रेणी के खिलाफ झूठी शिकायतें तथा कमेटी में सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। असंतोष के पीछे नियमों के उद्देश्य से अधिक उनके स्वरूप और व्याख्या को लेकर है। जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों का कहना है, इन प्रावधानों में अस्पष्टता है। शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया एकतरफा है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

सोनमर्ग में कुदरत का खौफनाक कहर, होटल इलाके के पास गिरा विशालकाय एवलांच

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग से हिमस्खलन (एवलांच) का एक बेहद डरावना वीडियो सामने आया है, जिसने सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग के होटल जोन के ठीक ऊपर पहाड़ों से अचानक बर्फ का एक विशाल सैलाब नीचे की ओर टूटकर गिरा। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे चंद सेकंड के भीतर बर्फ के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। वीडियो फुटेज में साफ नजर आता है कि ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से भारी मात्रा में बर्फ तेजी से नीचे की ओर खिसकती है। कुछ ही पलों में यह एक विशाल सफेद बादल की तरह फैल जाती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि इस भयानक घटना में किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने राहत की सांस लेते हुए बताया कि बर्फीला सैलाब होटल परिसर से कुछ ही दूरी पर रुक गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

तेजाब हमलों पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, कहा- दोषियों को सख्त सजा और संपत्ति जब्ती कानून बदले सरकार

नई दिल्ली। देश में बढ़ते तेजाब हमलों (एसिड अटैक) की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते

हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के लिए असाधारण दंडात्मक उपायों का जोरदार समर्थन किया है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को केंद्र सरकार को स्पष्ट सुझाव दिया कि तेजाब हमले जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए कानून में संशोधन पर गंभीरता से विचार किया जाए। अदालत का मानना है कि इन मामलों से ठीक उसी तरह सख्ती से निपटा जाना चाहिए जैसे दहेज हत्या के मामलों में निपटा जाता है, जहां अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी स्वयं आरोपी की होती है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि जब तक आरोपी के लिए सजा पीड़ादायक नहीं होगी, तब तक समाज में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाना कठिन है। पीठ ने कड़े शब्दों में कहा कि इस तरह के अपराधों में सुधारात्मक दंड की अवधारणा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सवाल उठाया कि ऐसे अपराधियों की संपत्ति क्यों नहीं जब्त की जा सकती? न्यायाधीशों का मानना है कि पीड़ितों को मुआवजा देने और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए आरोपी की संपत्ति कुर्क करने जैसे निवारक उपाय आवश्यक हैं।

आयुर्वेद में आधुनिक टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल बढ़ाना होगाः पीएम

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि बदलते समय के साथ तालमेल बिठाते हुए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और एआई, रोगों की पूर्वानुमान क्षमता बढ़ाने और उपचार के नए तरीकों को संभव बना सकते हैं। प्रधानमंत्री केरल में आर्य वैद्यशाला चैरिटेबल हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्य वैद्यशाला ने यह सिद्ध किया है कि परंपरा और आधुनिकता साथ-साथ आगे बढ़ सकती हैं और स्वास्थ्य सेवा लोगों के जीवन में विश्वास की मजबूत नींव बन सकती है। मोदी ने कहा कि आर्य वैद्यशाला ने आयुर्वेद की प्राचीन परंपराओं को सहेजते हुए आधुनिक आवश्यकताओं को अपनाया, उपचार पद्धतियों को सुव्यवस्थित किया और मरीजों तक प्रभावी सेवाएं पहुंचाईं। उन्होंने संस्थान की 125 वर्षों की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इसने आयुर्वेद को एक सशक्त उपचार प्रणाली के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने संस्थापक वैद्यरत्नम पी.एस. वारियर के योगदान को याद करते हुए कहा कि जनकल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी प्रेरणास्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्य वैद्यशाला भारत की उस उपचार परंपरा का जीवंत प्रतीक है जिसने सदियों से मानवता की सेवा की है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद कभी किसी एक काल या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा बल्कि हर युग में जीवन को समझने, संतुलन बनाने और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग दिखाता रहा है। उन्होंने बताया कि आज आर्य वैद्यशाला 600 से अधिक आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करती है और देश-विदेश में इसके अस्पताल 60 से अधिक देशों के मरीजों का उपचार कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि आर्य वैद्यशाला के लिए सेवा केवल विचार नहीं बल्कि भावना है, जो इसके कार्यों और संस्थानों में झलकती है। उन्होंने चैरिटेबल हॉस्पिटल के 100 वर्षों की निरंतर सेवा की सराहना की और वैद्यों, डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ तथा सभी कर्मचारियों को बधाई दी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत की विकास यात्रा और भविष्य की दिशा स्पष्ट : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को संसद के बजट सत्र की शुरुआत पर दोनों सदनों को राष्ट्रपति के संबोधन की सराहना करते हुए कहा कि यह संबोधन व्यापक, प्रेरक और दूरदर्शी रहा। राष्ट्रपति का संबोधन हाल के वर्षों में भारत की उल्लेखनीय विकास यात्रा को दर्शाने के साथ-साथ भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा भी तय करता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि संसदीय परंपराओं में राष्ट्रपति का संबोधन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह आने वाले महीनों में देश की विकास यात्रा को दिशा देने वाले नीतिगत संकल्पों को सामने रखता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह संबोधन देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में मार्गदर्शक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में 'विकसित भारत' के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया, जो मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण की हमारी साझा आकांक्षा को प्रतिबिंबित करता है। मोदी ने कहा कि संबोधन में सुधारों की रफ्तार को और तेज करने, नवाचार तथा सुशासन पर जोर देने की सामूहिक प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

यूजीसी के समानता नियमों की संवैधानिक वैधता पर बहस, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

एजेंसी। नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जता दी, क्योंकि शैक्षणिक परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए ढांचे को लेकर विवाद गहरा रहा है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी राहुल दीवान की ओर से वकील पार्थ यादव ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के समक्ष याचिका का जिक्र किया। यादव ने अदालत से मामले पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह कर कहा कि नियमों के लागू होने से भेदभाव होगा और इस मुद्दे पर तत्काल न्यायिक जांच की जरुरत है। उनके अनुरोध पर जवाब देकर मुख्य न्यायाधीश कांत ने सुनवाई की तारीख जल्द तय करने पर विचार करने की सहमति जाहिर की और वकीलों से याचिका में मौजूद सभी खामियों को दूर करने को कहा ताकि मामले को सूचीबद्ध किया जा सके। दीवान की याचिका उन कम से कम तीन चुनौतियों में से एक है जो 2026 के नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। इन नियमों को यूजीसी ने 13 जनवरी को अधिसूचित किया था और इसके तहत 2012 के ढांचे को प्रतिस्थापित किया था। इसमें से याचिका उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पोस्ट-डॉक्टरल शोधकर्ता मृत्युंजय तिवारी ने दायर की है। दूसरी याचिका मंगलवार सुबह अधिवक्ता विनीत जिंदल ने दायर की। अदालती कार्यवाही यूजीसी द्वारा अधिसूचित नए समानता नियमों पर चल रही व्यापक राष्ट्रीय बहस की पृष्ठभूमि में हुई। इन नियमों के तहत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और मान्यता प्राप्त संस्थानों में भेदभाव की शिकायतों के निवारण और समावेश को बढ़ावा देने के लिए समान अवसर केंद्र और समानता समितियां स्थापित करना अनिवार्य है। ये नियम अगस्त 2019 में उच्च शिक्षा में भेदभाव-विरोधी सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग वाली सर्वोच्च न्यायालय की याचिका का परिणाम हैं।

जनभागीदारी से मजबूत हो रहा जल संरक्षण, स्वच्छता का आंदोलनः सीआर

नई दिल्ली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले स्वच्छता योद्धाओं एवं स्कूली छात्रों के साथ संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनभागीदारी की भावना मजबूत हो रही है और समुदाय स्तर पर लोग जल संरक्षण एवं स्वच्छता के राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। पाटिल ने बुधवार को यहां पालिका सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट (पीएसओआई) में देशभर से आए स्वच्छता योद्धाओं और स्कूली छात्रों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में उन्होंने 25 जलज आजीविका केंद्रों का उद्घाटन किया। साथ ही यूथ फॉर गंगा-यूथ फॉर यमुना अभियान भी शुरू किया गया।

दिवंगत पूर्व सदस्यों और बांग्लादेश की पूर्व पीएम को श्रद्धांजली देकर संसद के दोनों सदन स्थगित

एजेंसी। नई दिल्ली

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समापन के बाद बुधवार को संसद के दोनों सदनों में दिवंगत पूर्व सदस्यों और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजली देकर कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पूर्व सदस्य एवं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को भी श्रद्धांजली दी गई। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति रखने के बाद शोक संदेश पढ़ा गया। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में विमान दुर्घटना में मारे गए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक प्रगट किया गया और उसके बाद दिवंगत पूर्व सदस्यों, शालिनी पाटिल, भानु प्रकाश, सत्येन्द्र नाथ ब्रह्मा चौधरी, सुरेश कलमाड़ी, कबीन्द्र पुरकायस्थ को श्रद्धांजली दी गई। बाद में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को श्रद्धांजली दी गई। इसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दूसरी ओर राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने पर पहले सदन के दिवंगत पूर्व सदस्यों पूर्व सदस्य एल. गणेशन और सुरेश कलमाड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक संदर्भ प्रस्तुत किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के बाद राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के तहत अधिसूचित एकसमान सहमति दिशा-निर्देशों में संशोधन

एजेंसी। नई दिल्ली

केन्द्र सरकार ने वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के तहत अधिसूचित एकसमान सहमति दिशा-निर्देशों में अहम संशोधन किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य उद्योगों को मिलने वाली पर्यावरणीय मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल बनाना, देरी कम करना और पर्यावरणीय अनुपालन को मज़बूत करना है। इस संशोधन से पिछले वर्ष जारी किए गए दिशा-निर्देश स्थापना सहमति (सीटीई) और संचालन सहमति (सीटीओ) प्रदान करने, अस्वीकार करने या रद्द करने के लिए की प्रक्रिया में एकरुपता आएगी। ये दिशा-निर्देश देशभर में सहमति प्रबंधन में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि बड़े सुधार के तहत कंसेंट टू ऑपरेट की वैधता अवधि में बदलाव किया गया है। अब एक बार जारी होने के बाद सीटूओ तब तक मान्य रहेगा, जब तक उसे किसी उल्लंघन की स्थिति में रद्द न किया जाए। इससे बार-बार नवीनीकरण की ज़रूरत खत्म होगी और उद्योगों को परिचालन में राहत मिलेगी। सरकार ने रेड कैटेगरी उद्योगों के लिए मंज़ूरी की समय-सीमा भी घटाकर 120 दिन से 90 दिन कर दी है। इसके अलावा, पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025 के तहत पंजीकृत पर्यावरण ऑडिटर को भी निरीक्षण और अनुपालन सत्यापन की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि माइक्रो और छोटे उद्योग को राहत देते हुए अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के लिए स्व-प्रमाणित आवेदन पर ही कंसेंट टू एस्टैब्लिश को स्वीकृत माना जाएगा। संशोधित गाइडलाइंस में अब न्यूनतम दूरी जैसे सख़्त मानकों की जगह स्थल-विशेष पर्यावरणीय आकलन को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही राज्य सरकारें 5 से 25 वर्षों के लिए एकमुश्त सीटूओ शुल्क तय कर सकेंगी। सरकार का कहना है कि ये संशोधन ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए देशभर में एक समान और पारदर्शी कंसेंट व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

भारत ग्लोबल राजनीति में टॉप पर पहुंचा जिसका यूरोप स्वागत करता हैः लेयेन

नई दिल्ली। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन के सम्मान में मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में डिनर आयोजित किया गया। इस दौरान उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि भारत ग्लोबल राजनीति में टॉप पर पहुंच गया है। यह एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसका यूरोप स्वागत करता है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत-यूरोप की सोच और नजरिया एक जैसा है। हमारा मानना है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना सिर्फ सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है। इस खास डिनर में पीएम मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल समेत कई हस्तियां शामिल हुईं। इस मौके पर उर्सुला ने कहा कि अगर यूरोप और भारत अपने संसाधनों और ताकत को मिलाएं, तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। इसी सोच के साथ आज दोनों साथ आए हैं।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEU-TICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

ख़ास ख़बर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अजित पवार के निधन पर दुख जताया

लोकतंत्र की शान, : नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार को विमान दुर्घटना में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य की मौत पर गहरा दुख जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में अजित पवार के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका आज अचानक विमान दुर्घटना में निधन होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद है। उनका सार्वजनिक जीवन काफी लंबा एवं प्रभावी रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हें हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य की बारामती एयरपोर्ट के नजदीक विमान दुर्घटना में मौत हो गयी।

एनडीसीटी नियम में अहम संशोधन, दवा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा

लोकतंत्र की शान, : नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स (एनडीसीटी) नियम, 2019 में अहम संशोधन अधिसूचित किए हैं। इनका उद्देश्य नियामकीय बोझ कम करना, अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना और दवा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। ये संशोधन प्रधानमंत्री के ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस और ट्रस्ट-आधारित नियमन के विज़न के अनुरूप किए गए हैं।

सत्यमेव जयते
Ministry of Ayush
Government of India

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गई जानकारी में बताया कि संशोधित नियमों के तहत अब दवाओं के गैर-व्यावसायिक निर्माण (जांच, अनुसंधान या विश्लेषण के लिए) के लिए पहले आवश्यक टेस्ट लाइसेंस की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह अब ऑनलाइन पूर्व-सूचना की व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि, यह छूट कुछ उच्च-जोखिम वाली दवाओं जैसे साइटोटॉक्सिक, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक पदार्थों पर लागू नहीं होगी। सरकार के अनुसार, इस सुधार से दवा विकास प्रक्रिया में कम से कम 90 दिनों की बचत होगी। वहीं, जिन मामलों में टेस्ट लाइसेंस की आवश्यकता बनी रहेगी, वहां इसकी प्रोसेसिंग समय-सीमा 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि हर साल सीडीएससीओ द्वारा लगभग 30 से 35 हज़ार टेस्ट लाइसेंस आवेदनों का निपटारा किया जाता है, ऐसे में यह बदलाव उद्योग के लिए बड़ी राहत होगी। क्लिनिकल रिसर्च को तेज़ करने के लिए सरकार ने कम जोखिम वाले बायोएवैलेबिलिटी/बायोइक्विवेलेंस अध्ययनों के लिए पूर्व अनुमति की शर्त भी हटा दी है। अब ऐसे अध्ययन केवल ऑनलाइन सूचना के आधार पर शुरू किए जा सकेंगे। सीडीएससीओ हर साल करीब 4,000 से 4,500 अध्ययन आवेदनों को प्रोसेस करता है। इन संशोधनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम और सुगम पोर्टल पर विशेष ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये बदलाव जन स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता किए बिना नियामकीय प्रक्रियाओं को तेज़ करेंगे, सीडीएससीओ की कार्यक्षमता बढ़ाएंगे।

वीरेंद्र सचदेवा ने अजीत पवार के निधन पर जताया दुख

लोकतंत्र की शान, : नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। सचदेवा ने कहा कि अजीत पवार का जाना बेहद दुखद है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार की भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। वह महाराष्ट्र के एक मजबूत नेता थे और उन्होंने भारतीय राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस तरह से उनका जाना बेहद दर्दनाक है। यह न केवल महाराष्ट्र के लोगों के लिए बल्कि खेल जगत के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि वह महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और लगातार खेल से जुड़े रहे।

बीटिंग रिट्रीट समारोहः विजय चौक, आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था में बदलाव

लोकतंत्र की शान, : नई दिल्ली। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के अवसर पर आयोजित होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के चलते 29 जनवरी को विजय चौक और उसके आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। यह समारोह विजय चौक पर आयोजित होगा। वहीं राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संसद भवन की रोशनी देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है।दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे।

इन सड़कों पर नहीं चलेगा आम यातायात

विजय चौक पूरी तरह आम यातायात के लिए बंद रहेगा।

रफी मार्ग (सुनहरी मस्जिद से कृषि भवन के बीच)।

रायसीना रोड (कृषि भवन से विजय चौक की ओर)।

दारा शिकोह रोड, कृष्णा मेनन मार्ग और सुनहरी मस्जिद से विजय चौक की ओर जाने वाले मार्ग, विजय चौक से 'सी' हेक्सागन के बीच कर्तव्यपथ। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को रिंग रोड, रिज रोड, अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमल अतातुर्क मार्ग, रानी झांसी रोड और मिंटो रोड जैसे वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। बस सेवाओं के रूट बदलेःसमारोह स्थल और इंडिया गेट के आसपास यातायात दबाव को देखते हुए डीटीसी और अन्य सिटी बसों के रूट में भी बदलाव किया गया है। दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक कई बसें अपने सामान्य मार्गों के बजाय पंचशील मार्ग, साइमन बोलिवर मार्ग, वंदे मातरम मार्ग, शंकर रोड, मंदिर मार्ग, कालीबाड़ी मार्ग और सफदरजंग रोड के रास्ते चलाई जाएंगी। कनॉट प्लेस, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, लाल किला और कश्मीरी गेट की ओर जाने वाली बसों के मार्ग भी बदले रहेंगे। कुछ बसों को शिवाजी स्टेडियम और उद्यान मार्ग पर ही समाप्त किया जाएगा।

पार्किंग की व्यवस्थाःबीटिंग रिट्रीट समारोह के बाद विजय चौक पर रोशनी देखने आने वालों के लिए शाम 7 बजे के बाद रफी मार्ग और 'सी' हेक्सागन के बीच जल चैनलों के पीछे पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता और वाहन चालकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी को दें। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे यात्रा की योजना पहले से बनाएं, अतिरिक्त समय लेकर निकलें और ट्रैफिक नियमों व पुलिस के निर्देशों का पालन करें। यातायात से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट, फेसबुक पेज, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर 8750871493 और हेल्पलाइन नंबर 1095 / 011-25844444 पर संपर्क कर सकते हैं।

गुरुग्राम में खुला नेचुरोपैथी और एक्यूपंक्चर का Rejua Energy Oasis, MLA बिमला चौधरी ने किया शुभारंभ

लोकतंत्र की शान

गुरुग्राम : गुरुग्राम में प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया और सशक्त अध्याय जुड़ गया है। Rejua Energy Oasis का भव्य शुभारंभ हरियाणा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती बिमला चौधरी के करकमलों द्वारा किया गया। इस विशेष वेलनेस सेंटर की स्थापना प्रसिद्ध एक्यूपंक्चर एवं नेचुरोपैथी विशेषज्ञ संतोष पांडेय ने की है, जहां मरीजों के लिए 1 दिन, 2 दिन और 5 दिन के विशेष हीलिंग पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं। Rejua Energy Oasis में कमर दर्द, घुटनों का दर्द, त्वचा रोग, गैस, सूजन, इंफ्लेमेशन, फ्रोजन शोल्डर, माइग्रेन, साइनस, सिर दर्द सहित कई पुरानी और जटिल बीमारियों का प्राकृतिक और समग्र उपचार किया जाएगा। यहां इलाज से पहले डॉक्टर नाड़ी देखकर बीमारी की पहचान करते हैं और उसी आधार पर उपचार पद्धति तय की जाती है। सेंटर में दिन की शुरुआत योग, ध्यान और हर्बल चाय से होती है। इसके बाद मरीज की समस्या के अनुसार मड थेरेपी, हॉट और ड्राई कपिंग, इंफ्रारेड थेरेपी, शिरोधारा, बस्ती, अदरक का लेप, मालिश और स्टीम थेरेपी जैसी प्रभावशाली उपचार विधियों से इलाज किया जाता है। उद्घाटन समारोह के दौरान संतोष पांडेय ने मुख्य अतिथि MLA बिमला चौधरी को एक्यूपंक्चर का लाइव डेमो देकर बताया कि सुई से दर्द नहीं होता, बल्कि दर्द से राहत मिलती है। मीडिया के सामने किए गए इस लाइव डेमो में एक पत्रकार, जिनका हाथ कई वर्षों से ऊपर नहीं उठ पा रहा था, उन्हें तुरंत राहत मिलती दिखाई दी। इस अवसर पर विधायक बिमला चौधरी ने Rejua Energy Oasis की सराहना करते हुए कहा, "संतोष पांडेय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन्हें इस नेक पहल के लिए बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि यह सेंटर लोगों की सेहत के लिए इसी तरह प्रभावी कार्य करता रहेगा।" कार्यक्रम में अभिनेत्री, मॉडल व इंफ्लुएंसर एकता जैन भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उनकी नाड़ी देखकर उपचार किया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा, "संतोष पांडेय जी वाकई कमाल हैं, इनकी सुई में जादू है।" इस मौके पर बेंगलुरु से आए प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट गौतम आजाद ने भी संतोष पांडेय को शुभकामनाएं दीं। साथ ही एडवोकेट राजपाल गुलिया, राजिंदर ड्रल्ल, सरपंच कुलदीप वशिष्ठ, अमित कटारिया, जोगिंदर जी, अशोक श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। Rejua Energy Oasis का उद्देश्य प्राकृतिक, सुरक्षित और समग्र चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ, संतुलित और तनावमुक्त जीवन की ओर प्रेरित करना है

अंकिता हत्याकांड की जांच को भटकाने का प्रयास कर रही उत्तराखंड की भाजपा सरकार- कांग्रेस

लोकतंत्र की शान, संवाददाता ज़ीशान अली

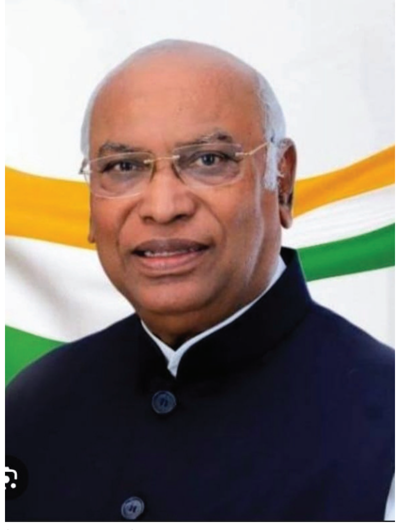

नई दिल्लीः कांग्रेस ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच को भटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की घोषणा के 15-17 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने वास्तव में सीबीआई को जांच सौंपने का औपचारिक प्रतिवेदन भेजा भी है या नहीं। कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि अंकिता भंडारी के माता-पिता की राय लेकर इस मामले में दोबारा जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान अंकिता के माता-पिता ने लिखित रूप में दोषियों को फांसी दिए जाने, मामले में शामिल वीआईपी का नाम उजागर किए जाने और सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। गोदियाल ने कहा कि यह स्वाभाविक था कि मामले में पीड़ित पक्ष, यानी अंकिता के माता-पिता के प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर सीबीआई जांच की संस्तुति की जाती। लेकिन सरकार ने पीड़ित परिवार की बजाय एक तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर सीबीआई जांच कराने की बात की, जिससे संदेह पैदा होता है कि जांच को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा सीबीआई को भेजा गया प्रतिवेदन अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह भी जानकारी मिल रही है कि सरकार नई एफआईआर के आधार पर इस मामले में वीआईपी के शामिल होने को एक काल्पनिक स्थिति बनाते हुए उसकी जांच करवाना चाहती है। जबकि यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि यथार्थ है कि एक वीआईपी को सर्विस देने से मना करने पर एक लड़की की जान ली गई है। जब कांग्रेस ने यह बात कही कि जांच इस यथार्थ की ही होनी चाहिए, तो सरकार ने कदम पीछे खींच लिए और अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी है या नहीं। सीबीआई की तरफ से भी इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है। भाजपा सरकार पर प्रभावशाली लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि इस मामले में आरोपियों द्वारा स्वयं नार्को टेस्ट की मांग किए जाने के बावजूद सरकारी पक्ष ने अदालत में इसका विरोध किया, जो आपराधिक मामलों में दुर्लभ है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस रुख से ऐसा लगता है कि उसे डर था कि नार्को टेस्ट से सत्ताधारी दल के नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेपी नड्डा जी से शिष्टाचार भेंट की

लोकतंत्र की शान

आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा जी से शिष्टाचार भेंट की । इस अवसर पर राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' (NHM) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेशवासियों को सुलभ और उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के संकल्प पर सार्थक संवाद हुआ।

60% मानसिक विकार अब 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में मिल रहा हैः इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली : इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी (ANCIPS 2026) के 77वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के मानसिक स्वास्थ्य की एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई, जहां प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने खुलासा किया कि भारत में लगभग 60% मानसिक विकार 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में पाए जाते हैं। उच्च स्तरीय वैज्ञानिक विचार-विमर्श के दौरान साझा किए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में मानसिक बीमारी अब जीवन के बाद के चरणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किशोरों, युवाओं और अपने सबसे उत्पादक वर्षों में लोगों को भी तेजी से प्रभावित कर रही है। चार दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 28 से 31 जनवरी तक यशोभूमि, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से हजारों मनोचिकित्सक, चिकित्सक, शोधकर्ता और नीति निर्माता एक साथ आए हैं। ANCIPS 2026 में विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मानसिक विकार अक्सर कम उम्र में ही प्रकट हो जाते हैं, अक्सर किशोरावस्था या युवावस्था के दौरान, और इनकी शुरुआत की औसत आयु 19 से 20 वर्ष के बीच होती है। सम्मेलन में प्रस्तुत वैश्विक और भारतीय अध्ययनों ने एक गंभीर तस्वीर पेश की है। मॉलिक्यूलर साइकियाट्री पत्रिका में प्रकाशित एक बड़े पैमाने के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में, जिसमें 7 लाख से अधिक व्यक्तियों पर नज़र रखी गई, यह दिखाया गया है कि 34.6 प्रतिशत मानसिक विकार 14 वर्ष की आयु से पहले, 48.4 प्रतिशत 18 वर्ष की आयु से पहले और 62.5 प्रतिशत 25 वर्ष की आयु तक शुरू हो जाते हैं। ये निष्कर्ष बताते हैं कि अधिकांश रोगियों के लिए, मानसिक बीमारी वयस्कता से बहुत पहले शुरू हो जाती है, और चुपचाप शिक्षा के परिणामों, करियर , रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। विशेषज्ञों ने बताया कि 25 वर्ष की आयु तक, अटेंशन डेफिसिट ह्यपेरेक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD), एंग्जायटी और खाने संबंधी विकारों के अधिकांश मामले सामने आ चुके होते हैं। डिप्रेशन, मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार और व्यवहार संबंधी लत भी पहले की तुलना में कम उम्र में ही सामने आ रहे हैं। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि जब मानसिक विकार कम उम्र में शुरू होते हैं और अनुपचारित रहते हैं, तो वे अक्सर दीर्घकालिक हो जाते हैं, जिससे दीर्घकालिक विकलांगता और महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक लागतें उत्पन्न होती हैं। ANCIPS 2026 दिल्ली के ऑर्गनाइसिंग सेक्रेटरी और होप केयर इंडिया के निदेशक डॉ. दीपक रहेजा ने कहा कि ये आंकड़े तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। "जब 60 प्रतिशत मानसिक विकार 35 वर्ष से कम आयु के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य संकट हमारी सोच से कहीं पहले ही सामने आ रहा है। ये वे वर्ष हैं जब व्यक्ति पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपना करियर बना रहे होते हैं और समाज में योगदान दे रहे होते हैं। शीघ्र पहचान, स्कूल और कॉलेज आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और कलंक मिटाना अब वैकल्पिक नहीं रह गए हैं; यदि हम अपने राष्ट्र के भविष्य की रक्षा करना चाहते हैं तो ये आवश्यक हैं।"

लोटस पेटल फ़ाउंडेशन ने अपनी ESG रिपोर्ट का किया शुभारंभ शिक्षा, समानता और सततता के प्रति प्रतिबद्धता को किया और सुदृढ़

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली : वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के जीवन को शिक्षा और समग्र विकास के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध एक गैर-लाभकारी संगठन, लोटस पेटल फ़ाउंडेशन ने आज अपनी पहली पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन (Environmental, Social and Governance – ESG) रिपोर्ट के शुभारंभ की घोषणा की। यह रिपोर्ट संगठन की संरचित जवाबदेही, पारदर्शिता और दीर्घकालिक सततता की दिशा में यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ESG रिपोर्ट का औपचारिक विमोचन लोटस पेटल फ़ाउंडेशन परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान किया गया, जिसमें कॉर्पोरेट जगत के नेता, सततता विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, विकास क्षेत्र के हितधारक तथा लोटस पेटल सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के छात्र—भविष्य के पथप्रदर्शक—उपस्थित रहे। इस अवसर ने फ़ाउंडेशन के इस विश्वास को पुनः स्थापित किया कि दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव की नींव जवाबदेही, मापनीय परिणामों और जिम्मेदार शासन पर आधारित होनी चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन समारोह से हुई, जिसके बाद छात्रों की प्रस्तुति और संस्थापक का संबोधन हुआ, जिसने उद्देश्य-प्रेरित कार्यों पर केंद्रित सुबह की दिशा तय की। ESG फ़िल्म के माध्यम से शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास के क्षेत्रों में लोटस पेटल के कार्यों को प्रदर्शित किया गया, साथ ही यह भी दिखाया गया कि किस प्रकार सततता के सिद्धांत उसके कार्यक्रमों, अवसंरचना और संचालन में अंतर्निहित हैं। मुख्य अतिथि, श्री संजीव सचर—एगॉन ज़ेंडर के पूर्व सीनियर पार्टनर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस व नेतृत्व परामर्श के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम—ने औपचारिक रूप से ESG रिपोर्ट का विमोचन किया और सामाजिक क्षेत्र में विश्वसनीय ESG ढाँचों के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। लोटस पेटल फ़ाउंडेशन की अपनी यात्रा को साझा करते हुए श्री सचर ने संगठन की गहरी मूल्य-आधारित संस्कृति की सराहना की। उन्होंने कहा, "जब कोई छात्र पृथ्वी की देखभाल करना चुनता है, तो यह एक गहरा परिवर्तन उत्पन्न करता है। सबसे महत्वपूर्ण सतत निवेश वह है जो हम अपने बच्चों में मूल्यों के रूप में करते हैं—और यही गुण यहाँ के हर छात्र में झलकता है।" उन्होंने अपने दिवंगत पिता के '4H सिद्धांत'—ईमानदारी (Honesty), विनम्रता (Humility), परिश्रम (Hardwork) और हास्य (Humour)—का उल्लेख करते हुए कहा कि इन चार स्तंभों के साथ "कुछ भी असंभव नहीं है।" इस अवसर पर बोलते हुए, लोटस पेटल फ़ाउंडेशन के संस्थापक एवं प्रबंध न्यासी श्री कुशल राज चक्रवर्ती ने कहा, "लोटस पेटल फ़ाउंडेशन के लिए ESG केवल अनुपालन का विषय नहीं है, बल्कि हमारे मूल्यों का प्रतिबिंब है। यह रिपोर्ट नैतिक, पारदर्शी और प्रभाव-संचालित प्रणालियों के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, ताकि हर साझेदारी और हर निवेशित रुपये से बच्चों और समुदायों के लिए सार्थक बदलाव सुनिश्चित हो सके।"

खजूरी खास में पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमले के मामले में नाबालिग आरोपित को पकड़ा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी पर चाकू से जानलेवा हमले के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एजीएस यूनिट ने एक नाबालिग को पकड़ा है। आरोपित पर उप्र पुलिस के एक जवान और उसकी मदद के लिए आए एक आम नागरिक पर चाकू से हमला करने का आरोप है। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने बुधवार को बताया कि घटना 22 जनवरी की रात करीब 8:30 बजे की है। खजूरी खास इलाके में बदमाशों के एक समूह ने उप्र पुलिस के एक जवान, जो थाना लोनी (गाजियाबाद) में तैनात था, पर हमला कर दिया। बीच-बचाव के लिए आए एक स्थानीय युवक पर भी चाकू से वार किया गया। हमले में पुलिसकर्मी के गले पर धारदार हथियार से गंभीर चोटें आईं, जबकि आम नागरिक के हाथ में चाकू लगा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में मेडिकल रिपोर्ट और घायल पुलिसकर्मी के बयान के आधार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। पुलिस उपायुक्त के अनुसार जांच और पहले से पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ के दौरान इस नाबालिग का नाम सामने आया, जिसने कथित तौर पर चाकू से हमला किया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच की एजीएस यूनिट को उसे पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुलिस टीम ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ जमीनी स्तर पर पूछताछ कर सुराग जुटाए। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित अपने रिश्तेदार से मिलने वेलकम इलाके में आने वाला है। सूचना के आधार पर जाल बिछाया गया और टीम ने नाबालिग आरोपित को दबोच लिया।

शांति सेवा न्याय
Delhi Police
SHANTI SEWA NYAYA

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद के ऐलान के बाद सिरसी रेलवे फाटक पर रहा पुलिस का कड़ा पहरा

लोकतंत्र की शान : सम्भल/सिरसी राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद द्वारा सम्भल से गजरौला रेल मार्ग की मांग को लेकर 28 जनवरी को सिरसी रेलवे फाटक पर ज्ञापन दिए जाने की सूचना दी गई थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। यह रेलवे क्रॉसिंग थाना हजरत नगर गढ़ी की सिरसी चौकी क्षेत्र में आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी हजरत नगर गढ़ी निरीक्षक सुधीर पवार एवं सिरसी चौकी प्रभारी मोहम्मद शाह फैसल के नेतृत्व में सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद द्वारा कार्यक्रम को रात में ही रद्द कर दिया गया था, जिसकी जानकारी प्रशासन को प्राप्त हो चुकी थी, इसके बावजूद पुलिस ने अपनी मुस्तैदी बरकरार रखी और पूरे समय क्षेत्र में सतर्क निगरानी जारी रखी गई। थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी द्वारा आने-जाने वाले लोगों पर लगातार नजर रखी गई, जिससे किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्र न हो सके और ज्ञापन देने जैसी कोई स्थिति नहीं बनने दी गई। उल्लेखनीय है कि सम्भल से गजरौला रेल मार्ग की मांग को लेकर सम्भलवासी काफी लंबे समय से आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक यह रेल लाइन धरातल पर नहीं उतर सकी है, जिसको लेकर आमजन में निराशा बनी हुई है। पुलिस प्रशासन की सतर्कता और प्रभावी व्यवस्था के चलते क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी रही। थाना प्रभारी सुधीर पवार एवं चौकी प्रभारी मोहम्मद शाह फैसल की सक्रिय भूमिका और कड़ी निगरानी के कारण किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गई।

नारी शक्ति संगठन में विद्यालय में कारपेट दान किया

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः हसनपुरः बुधवार को नगर की समाज सेवी संस्था नारी शक्ति संगठन के द्वारा नगर के विद्यालय राम मूर्ति पुरुषोत्तम शरन कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं को ठंड से बचने के लिए बिछाई हेतु कारपेट दान किया, इस मौके पर संगठन की महिलाओं ने कहा कि हमारा संगठन महिलाओं बालिकाओं के लिए हमेशा तत्पर है तथा हमारा संगठन विभिन्न सामाजिक कार्य करने में अग्रणी रहता है संगठन का उद्देश्य समाज की पीड़ित महिलाओं बच्चियों की मदद करना है, इस मौके पर अध्यक्षा डोली अग्रवाल, सीमा, शेफाली, रेखा, जया सिरोही आदि मौजूद रही 1

बिजनौर में भारतीय किसान संघ का जनपदीय ग्राम समीति सम्मेलन आयोजित किया गया

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः अमरोहाः बिजनौर बुधवार को बिजनौर के जे0वी0एस0 रिसोर्ट में भारतीय किसान संघ की जनपदीय ग्राम समीति सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अध्यक्ष के0 साई 0 रेड्डी व अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हरपाल जी व मेरठ प्रान्त के महामंत्री डा0 कुलदीप जी व प्रदेश संगठन मंत्री शिवकान्त जी जी ने किसान संघ के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया, के0 साई0 रेड्डी जी के जनपद बिजनौर में प्रथम बार आगमन पर हार्दिक स्वागत किया,सम्मेलन में मुख्य अतिथि के0साई0 रेड्डी जी ने ग्राम समीतियों से लेकर जिला स्तरीय समीतियों को मजबूत करने व किसानों की समस्याओं पर जोर दिया, कार्यक्रम की देखरेख प्रान्त संगठन मंत्री सुनील कुमार जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा,सम्मेलन के उपरान्त शहर बिजनौर में शभायात्रा निकाली गई, जगह जगह शोभायात्रा का स्वागत शहर वासियों नें किया। इस सम्मेलन में जनपद अमरोहा के जिलाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष शिवचरन सैनी, आलोक कुमार, जिला प्रचार प्रमुख अखिलेश शर्मा, प्रान्त कार्यकारिणी सदस्य महीपाल सिंह व जिला जैविक प्रमुख हरिप्रकाश राणा, बॉवी कुमार, राधेश्याम ,जिला कोषाध्यक्ष धर्मपालसिंह चौहान, हसनपुर खण्ड अध्यक्ष ओमवीरसिंह प्रशान्त भारद्वाज, जयप्रकाश शर्मा जीआदि सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे 1

स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित ओटी व एक्सरे मशीन को किया सील

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः हसनपुरः हसनपुर तहसील क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित क्लीनिक,अस्पताल आदि के खिलाफ कार्यवाही की जाए बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा chc प्रभावी डॉ धूर्वेंद्र सिंह के टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापे मार कर अवैध एक्सरे मशीन और ऑपरेशन थिएटर ओटी को सील कर दिया गया है, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी ऑपरेशन थिएटर नगर पंचायत उझारी में टीम ने कामिल नामक व्यक्ति के आसपास छापा मारा यहां बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से एक एक्सेल मशीन चलाई जा रही थी नियमों के उल्लंघन के कारण टीम ने मशीन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया इसी क्रम में हसनपुर नगर में सम्भल अड्डे पर स्थित आहद नर्सिंग होम की जांच की गई जांच के दौरान पाया गया कि यहां बिना पंजीकरण के एक ऑपरेशन थिएटर संचालित हो रहा है, विभाग टीम ने इस ऑपरेशन थिएटर O T को भी सील करने की कार्रवाई की, वही इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर ध्रुवेंद्र सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध चिकित्सा कार्य बर्दाशत नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा कि बिना वैध पंजीकरण के किसी भी ऑपरेशन थिएटर या एक्सरे मशीन का संचालन पूरी तरह गैरकानूनी है, उन्होंने बताया कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले केदो के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा, वही अवैध अस्पताल की ओटी सील होने से अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पताल केंद्रों के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है 1

नंगलिया मुंशी में हिंदू सम्मेलन का आयोजन महामंडलेश्वर ने दिया एकता का संदेश

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघक के स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा हरे शताब्दी वर्ष को लेकर क्षेत्र के गांव नंगलिया मुंशी स्थित सरस पैलेस में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें समाज को नई दिशा देने और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वक्ताओं ने सामाजिक कुरीतियों को त्यागकर राष्ट्र हित में एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर डॉ. स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि समाज की उन्नति तभी संभव है जब हम अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़े रहें। उन्होंने सामाजिक समरसता पर विशेष बल देते हुए कहा कि जाति-पाति के भेदभाव को भुलाकर एक सशक्त समाज का निर्माण करना ही आज की महती आवश्यकता है। महाराज ने पर्यावरण संरक्षण को धार्मिक कर्तव्य बताते हुए लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। विशिष्ट अतिथि विभाग प्रचारक संभल शरद कुमार और विहिप के विभाग संगठन मंत्री गौरव कुमार ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक मजबूती के लिए स्वदेशी उत्पादों का उपयोग अनिवार्य है। वक्ताओं ने उपस्थित जनसमूह को जागरूक करते हुए कहा कि हमें केवल अपने अधिकारों की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी पूरी निष्ठा से करना चाहिए। सम्मेलन की अध्यक्षता कृष्ण कुमार शर्मा ने की और कार्यक्रम का सफल संचालन रूपचंद चौहान द्वारा किया गया। आयोजन के दौरान वक्ताओं ने समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर राष्ट्र की तरक्की में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सचिन कुमार तहसील प्रचारक, सीता आर्या, करन सिंह, खड़क सिंह, टेकचंद चौहान, नरेंद्र चौहान, टिंकू चौहान, महिपाल सिंह,मा छत्रसिंह सैनी, मुरारी प्रजापति, रज्जन सिंह बाल्मीकि, रामरतन जाटव, कमल ठाकुर, उमेश सैन, बलवंत सिंह, वीर सिंह, संजीव चौहान,ओमवीर आदि मौजूद रहे

मुख्यमंत्री ने की गोसेवा, अपने हाथों से खिलाया गुड़-रोटी

लोक तंत्र की शान

गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान बुधवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने प्रातःकाल गोरखनाथ मंदिर में शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर मत्था टेका। सीएम योगी जब भी गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो गोसेवा भी उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा रहती है। मुख्यमंत्री सुबह मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गोशाला पहुंचे और वहां कुछ समय व्यतीत किया। गोशाला में सीएम योगी ने चारों तरफ भ्रमण करते हुए श्यामा, गौरी, गंगा, भोला आदि नाम पुकारे। उनकी आवाज इन गोवंश के लिए जानी पहचानी है। अपने नाम की प्यार भरी पुकार सुनते ही कई गोवंश दौड़ते-कूदते उनके पास आ गए। मुख्यमंत्री ने सभी के माथे पर हाथ फेरा, उन्हें खूब दुलारा और अपने हाथों से गुड़-रोटी खिलाया। बच्चों को स्नेहाशीष देकर बोले सीएम योगी, खूब पढ़ो-खूब बढ़ो मंदिर परिसर के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर जब परिजनों के साथ मंदिर आए बच्चों पर पड़ी तो उन्होंने बच्चों को अपने पास बुला लिया। बच्चों से उनका नाम और पढ़ाई के बारे में पूछा। उनसे ठिठोली भी की और फिर स्नेहाशीष देते हुए बोले, खूब पढ़ो-खूब आगे बढ़ो। मुख्यमंत्री ने इन सभी बच्चों को अपने हाथ से मिष्ठान्न भी दिया। इस अवसर पर उन्होंने दो छोटे बच्चों को गोद में लेकर उनका अन्नप्राशन भी कराया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जापान के यामानाशी प्रान्त के उप राज्यपाल ने की शिष्टाचार भेंट

लोक तंत्र की शान

लखनऊ :- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुधवार को जापान के यामानाशी प्रान्त के उप-राज्यपाल जुनिची इशिडोरा के नेतृत्व में आए आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत-जापान के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी और उत्तर प्रदेश तथा यामानाशी प्रान्त के बीच उभरते सहयोग को और आगे बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ आगमन पर जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और जापान के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, अनुशासन, नवाचार और सतत विकास जैसे साझा मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस साझेदारी को जमीनी स्तर पर साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। बैठक के दौरान वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार और यामानाशी प्रान्त के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष रूप से चर्चा हुई। यह एमओयू स्वच्छ ऊर्जा, खासतौर पर ग्रीन हाइड्रोजन, नवाचार, क्षमता निर्माण और सतत औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में सहयोग का मजबूत आधार प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 के माध्यम से निवेशकों के लिए एक स्पष्ट, पारदर्शी और अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। इस नीति के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी यूपीनेडा को सौंपी गई है।

कब्जामुक्त कराएं जमीन, बख्शे न जाएं भू माफियाः मुख्यमंत्री

लोक तंत्र की शान

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति की जमीन पर यदि किसी दबंग या भूमाफिया ने कब्जा किया है तो तत्काल जमीन को कब्जामुक्त कराया जाए। दूसरे की जमीन कब्जा करने वाले दबंगों, कमजोरों को उजाड़ने वालों तथा भूमाफिया को कतई न बख्शा जाए। उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, सबक सिखाया जाए। सीएम ने दोहराया कि सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। सीएम योगी बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में कुर्सियों पर बैठे लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर सबकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित व संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जनता दर्शन में दबंगों द्वारा जमीन कब्जा किए जाने की एक शिकायत पर मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद प्रशासन व पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया कि जमीन कब्जा की शिकायत पर त्वरित एक्शन लिया जाए। जमीन कब्जामुक्त होनी चाहिए, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दबंग किसी की जमीन पर कब्जा न करने पाए। जनता दर्शन में कुछ महिलाओं ने ससुराल पक्ष से विवाद तथा परिवार से जुड़ी शिकायतें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। सीएम योगी ने इन शिकायतों पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के साथ संवाद कर समस्या का समाधान कराया जाए। ऐसा न होने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी मदद की जाए।

25 करोड़ की आबादी को परिवार मानकर बढ़ाया विकास अभियान : मुख्यमंत्री

लोक तंत्र की शान

सिद्धार्थनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव का बुधवार को शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 1052 करोड़ रुपये की 229 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि हमने 25 करोड़ की आबादी को परिवार मानकर विकास कार्य आगे बढ़ाए हैं। बीमार मानसिकता वाले लोगों ने इस क्षेत्र को बीमार कर दिया था, लेकिन हमने दृढ़ संकल्प से बीमारी दूर कर दी। अब हम उपद्रव से उत्सव प्रदेश की तरफ भी बढ़ चुके हैं। सीएम ने बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक-शिक्षिकाओं की सरस्वती वंदना को सराहते हुए कहा कि जब ऐसे संस्कार बच्चों में जाएंगे तो वे विकसित भारत की संकल्पना के वाहक बनेंगे। इस अवसर पर सरकारी योजनाओं की मदद से सफलता हासिल करने वाली दो महिला उद्यमियों ने मंच पर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी कहानी साझा की।

सरकार बिना भेदभाव दे रही पैसा, जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों से लागू हो रहीं योजनाएं-सीएम योगी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों, प्रयासों से जनपद में योजनाएं लागू हो रही हैं। सरकार निमित्त मात्र है, हम बिना भेदभाव पैसा दे देते हैं। हमने 25 करोड़ की आबादी को परिवार मानकर विकास के अभियान को बढ़ाया है। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय व सपा विधायक सैयदा खातून को इस आयोजन में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया और आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन हताशा-निराशा के लिए नहीं, बल्कि उत्साह-उमंग और एक-दूसरे के साथ मिलकर विकास के अभियान को बढ़ाने के लिए मिला है। हर जगह काट-छांट नहीं होनी चाहिए। प्रयास अच्छी सोच के साथ प्रारंभ करें।

बांटकर विकास नहीं कर सकती सरकार - सीएम योगी ने कहा कि सरकार बांटकर विकास नहीं कर सकती। अपने-पराये, जाति, मत-मजहब, क्षेत्र व भाषा के रूप में भेदभाव न हो बल्कि समग्रता, सतत विकास के भाव से कार्य हो। सतत विकास की दृष्टि से किया गया प्रयास ही रामराज्य की अवधारणा का साकार रूप है। विकास का आधार हर तबका, गांव, गरीब, किसान व युवा होना चाहिए। बिना भेदभाव हर गरीब को राशन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलना चाहिए। सरकार की योजनाएं गरीबों, महिलाओं, युवाओं व किसानों को फोकस करते हुए बनी हैं। हमने 'सबका साथ-सबका विकास' के आधार पर नागरिकों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया। सीएम ने 'विकसित भारत जी राम जी' योजना के फायदे भी बताए।

राजा टोडरमल स्मारक समिति, राजस्व सुरक्षा सेवादल दल के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी को किया सम्मानित

लोक तंत्र की शान

देवेंद्र सिंह,सीतापुर /राजा टोडरमल स्मारक समिति, राजस्व सुरक्षा सेवादल दल (RSSD) के पदाधिकारियों ने सीतापुर जिला अधिकारी राजा गणपति आर को राजस्व जनक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। राजा टोडरमल स्मारक समिति राजस्व सुरक्षा सेवादल के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजयपुरी ने जिला अधिकारी को लहरपुर निरीक्षण करने जाते समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था,जिसमे वह बच बाल बाल गए ,उनसे कुशल क्षेम जाना,उनको स्वास्थ रहने का आशीर्वाद दिया,कहा आप गरीबों की हर संभव मदद करते हैं,जो बहुत नेक कार्य हैं,सबका आशीर्वाद आपके साथ है। आगामी 10 फरवरी 20 26 को राजस्व जनक राजा टोडरमल जी की जयंती सम्मान समारोह के अवसर पर जिला अधिकारी को आमंत्रित किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी सन्तोष कुमार राव,पप्पू गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

अग्रवाल सभा की बैठक में U G C कानून को लेकर रोष प्रकट किया गया

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः मंगलवार की देर श्याम नगर की समाजसेवी संस्था अग्रवाल सभा हसनपुर (संबद्ध अग्रोहा धाम) की मासिक बैठक नगर के एक रेस्टोरेंट में आयोजित की गई जिसमें यूजीसी कानून को लेकर वक्ताओं ने रोष प्रकट किया, बैठक में यूजीसी कानून से स्वर्ण वर्ग को होने वाले नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार से इस काले कानून को वापस लेने की मांग की गई तथा जल्द ही सर्व समाज के साथ मिलकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित करते हुए उप जिला अधिकारी को दिए जाने पर विचार विमर्श किया गया, वहीं बैठक की अध्यक्षता उमेश अग्रवाल ने की तथा कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र गोयल ने अग्रवाल सभा हसनपुर द्वारा 2025 में किए गए वार्षिक उत्सव का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया, वहीं बैठक में अग्रवाल सभा हसनपुर द्वारा होली के पावन अवसर पर होली मिलन समारोह (फूलों की होली) कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर सहमति बनी, बैठक में वक्ताओं ने कहा कि यदि केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी जैसे काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो अग्रवाल सभा हसनपुर पूरे जिले के स्वर्ण समाज के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करेगी, इस मौके पर मुख्य रूप से अग्रवाल सभा के संस्थापक अध्यक्ष डॉ शिवचरण दास अग्रवाल, नगर अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, महामंत्री मुकेश गोयल, कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र गोयल,अनुराग अग्रवाल, मनोज गोयल, सुनील अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, पौरुष अग्रवाल, अक्षी अग्रवाल, राजेश कुमार, सागर अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, अनुपम अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, मधुर अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, प्रवीन अग्रवाल, मयंक अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, अमित अग्रवाल उर्फ निक्कू, वेद प्रकाश अग्रवाल, युवा नगर अध्यक्ष तरुण अग्रवाल, युवा महामंत्री अक्षय अग्रवाल आदि अग्रवाल सभा के सदस्य एवं पदाधिकारी गण मौजूद रहे 1

मुसहर, वनटांगिया, बुक्सा और बावरिया बने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई ताकत

लोक तंत्र की शान

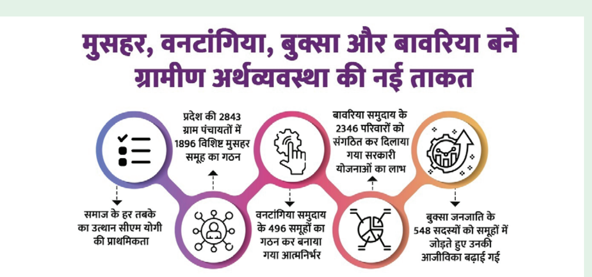

लखनऊः उत्तर प्रदेश के वंचित समुदाय जिन्हें कल तक बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, आज वही मुसहर, वनटांगिया, बावरिया और बुक्सा समुदाय की महिलाएं और पुरुष 'आत्मनिर्भर' बनकर विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों से लेकर सुदूर जंगलों तक, योगी सरकार की मुहिम ने इन परिवारों को न केवल सरकारी योजनाओं से जोड़ा, बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान और सम्मान भी दिलाया है।

वंचित समुदायों के दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश तभी 'उत्तम प्रदेश' बनेगा, जब राज्य का सबसे कमजोर व्यक्ति सशक्त होगा। इसी सोच के तहत इन विशिष्ट समूहों को स्टार्ट-अप फंड, रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इससे वे साहूकारों के चंगुल से मुक्त होकर खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश हैं कि वंचित समुदायों के दरवाजे तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए।

मुसहर समुदाय : 2843 ग्राम पंचायतों में जगी नई उम्मीद-कभी समाज की मुख्यधारा से पूरी तरह कटे हुए मुसहर समुदाय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। प्रदेश की 2843 ग्राम पंचायतों में इस समुदाय को संगठित किया गया है। यहां 1896 विशिष्ट मुसहर समूहों का गठन किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन परिवारों को सीधे स्वरोजगार और सरकारी अनुदान से जोड़ा गया है, जिससे दशकों से चला आ रहा पलायन और गरीबी का चक्र टूटा है।

वनटांगिया और बुक्सा : जंगलों से निकलकर बाजार तक का सफर-आजादी के बाद भी लंबे समय तक बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले वनटांगिया समुदाय के 496 समूहों का गठन किया गया है। इन्हें न केवल राजस्व ग्राम का अधिकार मिला, बल्कि अब ये समूह आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं। इसी प्रकार, बुक्सा जनजाति के 548 सदस्यों को भी समूहों में जोड़कर उनके पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाजार से जोड़ा गया है, जिससे उनकी आजीविका में बड़ा उछाल आया है।

संक्षिप्त समाचार

कारोबारी को कफन भेजा, कहा-तुम्हारा मर्डर करेंगे, लेटर में लिखा- राजपूत हूं, प्रण लिया है तो पूरा करूंगा

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली में एक कारोबारी को जान से मारने के धमकी मिली है। ये धमकी एक लेटर में दी गई है। लेटर के साथ कफन भी भेजा गया है। धमकी देने वाले ने लिखा है- 'रतन तुम जितना भी छिप कर रह लो, हम तुमको जान से मार देंगे। आज हो, कल हो, महीना हो, साल हो, 2 साल हो, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे।' लेटर के अंत में लिखा है- 'रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम्हें एक छोटा गिफ्ट भेजा है, जो तुम्हें मरने के बाद काम आएगा।' जिस कारोबारी को धमकी मिली है उसका नाम रतन चौधरी है। उनकी महुआ थाना क्षेत्र स्थित महुआ पुरानी बाजार में दुकान है। ये लेटर और कफन उनके छोटे भाई के घर फेंका गया है। धमकी मिलने के बाद पूरा परिवार दहशत में है। धमकी भरा पत्र और कफन मिलने के बाद परिजनों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। परिवार का कहना है कि डायल 112 की टीम ने यह कहकर कार्रवाई से इनकार कर दिया कि जब पत्र फेंकने वाला अज्ञात है, तो वे क्या कर सकते हैं। पुलिस ने परिजनों को थाने में आवेदन देने की सलाह दी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने स्थानीय महुआ थाने से संपर्क किया। थाना अध्यक्ष ने भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्र फेंके जाने की बात कहते हुए कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने परिजनों को DSP से मिलने या अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराने की सलाह दी। पीड़ित परिवार ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 1 जनवरी को भी उनके घर पर इसी तरह का धमकी भरा पत्र फेंका गया था। उस समय पुलिस ने उन्हें CCTV कैमरे लगवाने की सलाह दी थी।

मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर खाली कराया गया

बम निरोधक और डॉग स्क्वायड की टीम कर रही जांच

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा को देखते हुए तत्काल प्रभाव से पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। जानकारी के अनुसार, कोर्ट प्रशासन को एक धमकी भरा ई-मेल मिला। इसमें मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर में सिलसिलेवार बम धमाके की बात कही गई थी। इस धमकी के बाद जिला जज ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए तत्काल कोर्ट परिसर खाली करने का निर्देश जारी किया। जिला जज के आदेश पर पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। कोर्ट में चल रही सभी न्यायिक प्रक्रियाओं को फिलहाल रोक दिया गया है। सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ते (BDDS) और डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया गया है। पुलिस की टीम परिसर के चप्पे-चप्पे की सघन तलाशी ले रही है।

कोर्ट के प्रवेश द्वारों को सील कर दिया गया है और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। एसएसपी समेत जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वयं सुरक्षा व्यवस्था और जांच अभियान की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ई-मेल के स्रोत की जांच की जा रही है और साइबर सेल की टीम धमकी भेजने वाले का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल, पूरे परिसर को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जांच पूरी होने और सुरक्षा के बाद ही कोर्ट में कामकाज सामान्य रूप से शुरू हो सकेगा।

बेउर मोड़-दीदारगंज एलिवेटेड-एटग्रेड रोड बनाने पर केंद्र-राज्य के बीच ठनी

लोकतंत्र की शान : पटना। बेउर मोड़-दीदारगंज (न्यू बाइपास) 17 किमी लंबे एलिवेटेड/एट ग्रेड रोड बनाने पर केंद्र-राज्य सरकार के बीच ठन गई है। केंद्र सरकार की एजेंसी एनएचएआई ने जीएसटी, रायल्टी और यूटिलिटी शिफ्टिंग खर्च उठाने से इनकार कर दिया है। यह राशि राज्य के पथ निर्माण विभाग को देने को कहा है। केंद्र ने इस पर राज्य सरकार से सहमति मांगी है। केंद्र ने कहा है कि इन मामलों पर फैसला नहीं होने के कारण ही इस अहम प्रोजेक्ट के टेंडर में देरी हो रही है। राज्य सरकार शीघ्र फैसला कर केंद्र को अवगत कराए। उधर, पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इसे मानने पर निर्माण राशि के 9% स्टेट जीएसटी, निर्माण में लगने वाले मिनरल बालू, गिट्टी आदि की रायल्टी और यूटिलिटी शिफ्टिंग (बिजली पोल, पानी सप्लाई लाइन, निकायों की संपत्तियां आदि के भुगतान में लगने वाली करीब 308 करोड़ की राशि) पर करीब 500 करोड़ खर्च होंगे। अभी इस दूरी तय करने में गाड़ियों को 1 से 1.5 घंटा का समय लगता है। कारण, न्यू बाइपास की दोनों तरफ सैकड़ों नई कॉलोनियां बस गई हैं, जिनमें लाखों की आबादी रह रही है। उन कॉलोनियों की सड़कों से न्यू बाइपास पर दिनभर गाड़ियां चढ़ती रहती हैं। पटना एम्स से बेउर मोड़ आने में भी जाम मिलता है। ट्रकों और अन्य बड़े मालवाहक वाहनों को अनीसाबाद से दीदारगंज की तरफ जाने में भारी परेशानी होती है।

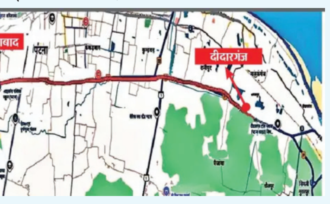

खासकर अनीसाबाद मोड़, 90 फीट मोड़, भूतनाथ रोड मोड़, पहाड़ी मोड़ समेत कई मोड़ पर दिनभर जाम लगा रहता है। एलिवेटेड रोड बनने पर मालवाहक वाहनों का डीजल और समय बचेगा। साथ ही न्यू बाइपास की दोनों तरफ बसी कॉलोनियों के लोगों को सड़क पर करने में सुविधा होगी।

केंद्र ने 3500 करोड़ निर्माण राशि तय की: वहीं एम्स से बेउर मोड़ तक 10 किमी 4/6 लेन लंबे एलिवेटेड रोड बनाने के लिए 1308 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है। बेउर मोड़ से आगे सरिस्ताबाद से दीदारगंज तक 17 किमी सिक्स लेन एलिवेटेड/एट ग्रेड रोड बनाने के लिए केंद्र ने 3500 करोड़ की राशि तय की है।

दियारा में एसपी का औचक निरीक्षण, तीन थानों की जांच, लंबित केस जल्द निपटाने का निर्देश

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली के पुलिस अधीक्षक (SP) ने आज दियारा क्षेत्र के तीन थानों - रुस्तमपुर, जुड़ावनपुर और राघोपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना अभिलेखों की गहन समीक्षा की। एसपी ने लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन और क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अपराध नियंत्रण और तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई में कोई कोताही न बरतने की स्पष्ट चेतावनी भी दी।

पूर्ण अंकुश लगाने का आदेश दिया: विशेष रूप से, दियारा क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण पर पूर्ण अंकुश लगाने का आदेश दिया गया। साथ ही, शराब भट्ठियों को ध्वस्त करने हेतु निरंतर विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, पुलिस अधीक्षक ने रुस्तमपुर थाने के निर्माणाधीन भवन का भी जायजा लिया। उन्होंने भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को पुलिस-पब्लिक संबंध बेहतर बनाने और थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए भी निर्देशित किया।

पटना: यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन

लोकतंत्र की शान , पटना

❑ **पीएम के पोस्टर जलाए-कालिख पोती कहा- परशुराम की तरह गरजेंगे, फरसा लेकर उतरेंगे**

UGC बिल 2026 को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहा है। पटना में इसके खिलाफ ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन और सवर्ण समाज एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन करने वालों ने PM मोदी और अमित शाह के पोस्टर लगाए गए। कालिख भी पोती गई। उनका कहना है कि ये काला कानून है। इसे तत्काल वापस लें। प्रदर्शन कर रहे उज्ज्वल कुमार ने कहा, 'यूजीसी का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून कहीं से बच्चों के हित में नहीं है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम लोग समानता का काम कर रहे हैं और दूसरे तरफ आप जातीय उन्मूलन में बच्चों को फैला रहे हैं। अगर समानता करते तो बच्चों के लिए ये कानून क्यों लाते।

दिनकर से एक बार जाति पूछी गई थी तो उन्होंने गरजते हुए स्वर में कहा था कि सिमरिया घाट का जलता हुआ अंगार हूं मैं, जाति से भूमिहार हूं मैं, पूजा भले हम स्वर्ण लोग राम की करते हैं, बाकी परशुराम की तरह गरजते है। जब जरूरत पड़ेगा तो फरसा लेकर रोड़ पर उतरेंगे। चक्काजाम करेंगे। इस यूजीसी कानून का हम लोग विरोध करते हैं। मोदी सरकार को समझना होगा की ये जो स्वर्ण है, लोगों को सत्ता पर बैठाने का काम भी करता है और उतारने का भी काम करता है।' इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। राजद और तेजप्रताप यादव ने खुलकर UGC बिल का समर्थन किया है। वहीं, भाजपा और उसके सहयोगी दलों की चुप्पी पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं।

राजद का समर्थन, आरक्षित वर्गों के लिए 'सुरक्षा कवच' बताया: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने यूजीसी कानून 2026 का खुलकर समर्थन किया है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि, यह कानून आरक्षित वर्गों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आती रही हैं, जिस पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर यह कानून लाया गया है।

बिहार सरकार ने दिए पुनर्विचार के संकेत: बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार सिंह ने यूजीसी के नए प्रावधानों को लेकर हो रहे विरोध पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। मंत्री ने याद दिलाया कि इससे पहले भी कई नियम विरोध और सुझावों के बाद बदले गए हैं।

यूजीसी बिल को तेज प्रताप यादव का खुला समर्थन: राजद नेता तेज प्रताप यादव ने यूजीसी के नए नियमों को ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लाए गए "Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026" कानून का मकसद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकना है।'

कांग्रेस ने उठाए एकतरफा चर्चा पर सवाल: कांग्रेस ने UGC बिल को लेकर हो रही चर्चाओं को एकतरफा बताया है। पार्टी का कहना है कि यह समझने की जरूरत है कि इस कानून का दुरुपयोग आखिर क्यों और कैसे किया जाएगा। कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या इस तरह की अफवाहें फैलाकर देश में अराजकता का माहौल नहीं बनाया जा रहा।

मत्स्य डेयरी एवं पशुपालन मंत्री सह जिला प्रभारी सुरेंद्र मेहता के कटिहार आगमन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

लोकतंत्र की शान, सुमन सिंह कटिहार

कटिहार: जिला अतिथि गृह में बिहार सरकार के मत्स्य डेयरी एवं पशुपालन मंत्री सह कटिहार जिला प्रभारी मंत्री श्री सुरेंद्र मेहता जी के प्रथम आगमन के अवसर पर उनका पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर संगठनात्मक मजबूती केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जिले के सर्वांगीण विकास को लेकर सार्थक चर्चा हुई। स्वागत कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी सह कोसी स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित विधान परिषद प्रतिनिधि हितेश कुमार शर्मा जिला कार्य समिति सदस्य विजय कुमार सिंह भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजेश ठाकुर भाजपा पूर्व जिला महामंत्री काजल मित्रा सहित भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने माननीय मंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

जिला प्रशासन ने नोटिस दिया, अतिक्रमण हटेगा

लोकतंत्र की शान , पटना

♦ **बांसघाट के सामने पांच एकड़ जमीन पर 86 लोगों का कब्जा**

बांसघाट के सामने 5 एकड़ सरकारी जमीन पर 81 लोगों का कब्जा है। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम के निर्देश पर सदर अंचल कार्यालय ने इनलोगों को नोटिस जारी किया है। 5 फरवरी को सदर अंचलाधिकारी रजनीकांत द्वारा सुनवाई की जाएगी। नोटिस पाने वाले लोगों को जमीन से जुड़े दस्तावेज लाने को कहा गया है। साक्ष्य और दस्तावेजों की जांच कर सीओ द्वारा आदेश पारित किया जाएगा। इसके बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा।

जिला प्रशासन के मुताबिक, बुद्धा कॉलोनी मोड़ से काली मंदिर तक की जमीन गैरमजरुआ आम है। इस जमीन पर सरकार का अधिकार है। इस पर लोगों ने वर्षों से कब्जा कर रखा है। कुछ पक्का मकान और कच्चा निर्माण हैं। इस पांच एकड़ जमीन के उत्तर में अशोक राजपथ, दक्षिण में मंदिरी और बुद्धा कॉलोनी का हिस्सा, पूरब में काली मंदिर और पश्चिम में बुद्ध कॉलोनी रोड है।

यहां वेंडिंग जोन बनेगा: इस पांच एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाकर बड़े वेंडिंग जोन का निर्माण होगा। साथ ही अन्य सरकारी बिल्डिंग, पार्क आदि के निर्माण की योजना है। जिला प्रशासन के मुताबिक, शहर के अंदर इतने बड़े भूखंड का लाभ सार्वजनिक रूप से नहीं मिल रहा है। अतिक्रमण हटने के बाद इसकी उपयोगिता के आधार पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

बिहार में 4 हजार टीचर्स और हजारों बच्चों का प्रशिक्षण, आपदा से बचाव की बड़ी तैयारी

लोकतंत्र की शान , पटना

❑ **1352 दिव्यांग बच्चों को भी मिली ट्रेनिंग**

बिहार सरकार के निर्देश के अनुसार हर महीने के आखिरी बुधवार को सभी विभाग अपने-अपने कामकाज की जानकारी पीसी कर दे सकते हैं। आज सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव मोहम्मद गफ्फार ने बताया कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) द्वारा राज्यभर में आपदा से बचाव को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल होगा तैयार: उन्होंने बताया कि दिव्यांग बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसके तहत दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। अब तक करीब 1352 दिव्यांग बच्चों को तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण देकर आपदा से बचाव की जानकारी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के सहयोग से राज्य के सभी सरकारी, निजी स्कूल और मदरसों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को आपदा के खतरे पहचानने और उससे बचाव के उपाय सिखाना है। वर्ष 2025 में 4363 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 1057 मध्य विद्यालय और 3306 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शामिल हैं। साथ ही 1005 मदरसों की फोकल शिक्षिकाओं को भी प्रशिक्षण दिया गया।

सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की शुरुआत: डूबने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक डूबने से होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत की कमी लाना है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों, किशोरों और युवाओं को तैराकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 16374 युवकों और युवतियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा 96 मास्टर ट्रेनर्स भी तैयार किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा जागरूकता के लिए 5 जिलों के 483 ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वयकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। वहीं 2241 आंगनवाड़ी सेविकाओं और 482 स्वास्थ्य कर्मियों को भी आपदा प्रबंधन से जुड़ा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए पटना में करीब 5000 मजदूर और श्रमिक वर्ग के लोगों को जागरूक किया गया। अंत में सचिव ने बताया कि जीविका दीदियों के लिए भी आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़े चार विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, ताकि वे आपदा के समय बेहतर भूमिका निभा सकें।

बगहा, बक्सर में तेज बारिश, 5 जिलों में अलर्ट, पटना समेत 10 शहरों में छाए बादल

लोकतंत्र की शान , पटना

पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से बिहार में भी फिर से ठंड बढ़ सकती है। पूर्वी चंपारण, सहित 5 जिलों में आज बारिश हो सकती है। बगहा में तेज बारिश हुई है। बक्सर में बूंदाबांदी हुई। वहीं सुपौल, समस्तीपुर में बादल छाए हुए हैं। जबकि औरंगाबाद, बेतिया, सुपौल समेत 10 जिलों में सुबह कोहरा छाया रहा।

मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 जनवरी से बिहार के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। संभावित जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना और बेगूसराय शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, कोहरे की यह स्थिति 29 जनवरी से अगले 2 से 3 दिनों तक बनी रह सकती है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ कोहरा धीरे-धीरे छंटने और धूप निकलने की संभावना है।

पटना में सुबह के समय छाया रहेगा हल्का कोहरा: राजधानी पटना में सुबह के समय हल्का कोहरा छाने और ठंड का असर महसूस किया जा सकता है। दिन में धूप निकलने से तापमान सामान्य रहेगा। बीते 24 घंटे में पटना का अधिकतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देर शाम और सुबह ठंड अधिक रही, जबकि दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा में ठंडक बनी रही।

बिहार का मौसम अचानक क्यों बदला?: मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बिहार में इस समय मौसम में उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है। उत्तर-पश्चिम भारत से सक्रिय यह मौसमी सिस्टम अपने साथ नमी लेकर आ रहा है, जिसका असर खासकर बिहार के उत्तरी जिलों में देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे कुछ जिलों में बारिश की स्थिति बन रही है। वहीं, रात के तापमान में गिरावट और हवा में बढ़ी नमी के कारण सुबह और शाम ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है।

5-8 फरवरी तक वसंतोत्सव कला कार्यशाला 11 से 29 साल के युवा ले सकेंगे हिस्सा

लोकतंत्र की शान , पटना

सिखाई जाएगी टिकुली और सिक्की कला

पटना में जिला कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से वसंतोत्सव कला कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को टिकुली कला और सिक्की कला सिखाई जाएगी। यह कार्यशाला 5 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक बिहार ललित कला अकादमी, पटना में होगी। इसका आयोजन कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार और जिला प्रशासन पटना मिलकर कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार की पारंपरिक लोक कलाओं-विशेष रूप से टिकुली कला और सिक्की कला को संरक्षित और प्रोत्साहित करना है।

11 से 29 साल के युवा ले सकते हैं हिस्सा: इस कार्यशाला में 11 साल से 29 साल तक के लड़के-लड़कियां भाग ले सकते हैं। इसमें स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राएं भी शामिल हो सकते हैं। आवेदन करने के लिए जारी किए गए QR कोड को स्कैन करना होगा। फॉर्म भरने के बाद उसे जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय, पटना में जमा करना होगा। चाहें तो आवेदन ईमेल आईडी daco.ptna@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

3 फरवरी तक करना होगा आवेदन: आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 फरवरी 2026 दोपहर 3 बजे तक रखी गई है। इसके बाद कोई फॉर्म नहीं लिया जाएगा। आप अपना भरा हुआ फॉर्म जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय, तृतीय तल, जिला विकास भवन, समाहरणालय, पटना (गांधी मैदान के पास) जमा कर सकते है।

पारंपरिक कला को मिलेगा बढ़ावा: इस कार्यशाला में एक्सपर्ट कलाकारों से सीधे टिकुली और सिक्की कला सीखने का मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ आपकी कला निखरेगी, बल्कि आगे चलकर इससे रोजगार या स्वरोजगार का रास्ता भी खुल सकता है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी ने बताया कि इस तरह की कार्यशालाओं का मकसद युवाओं को अपनी पारंपरिक कला से जोड़ना और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना है।

बदलते मौसम से अस्पतालों में मरीजों की बढ़ी भीड़, पटना में वायरल बुखार

लोकतंत्र की शान , पटना

मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव के कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ बढ़ गई है। दिन में धूप और सुबह-शाम ठंड के चलते OPD में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दिन में हल्की गर्मी और सुबह-शाम के समय कनकनी महसूस की जा रही है। ऐसे में कई लोग ठंड को लेकर लापरवाह हो रहे हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम के बढ़े मरीज: सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी क्लीनिकों तक में वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी, एलर्जी, सांस के मरीज, बदन दर्द, जोड़ों के दर्द और हृदय रोग से पीड़ित अस्पताल पहुंच रहे हैं। मौसम का यह परिवर्तन श्वास, ब्लड प्रेशर और हृदय रोगियों के लिए अधिक घातक साबित हो रहा है। पिछले एक सप्ताह से वायरल बुखार का प्रकोप तेजी से फैला है। यह बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। बुखार उतरने के बाद भी अधिकांश मरीजों को कमजोरी, खांसी और गले में तेज दर्द की शिकायत है।

❑ **सर्दी-खांसी के मामले बढ़े, विशेषज्ञ बोले- ठंड को लेकर लापरवाही से बचें**

बदलते मौसम को लेकर क्या कहते हैं डॉक्टर?: गार्डिनर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि, 'मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिससे मरीजों की संख्या में काफी बढ़ी है। बदलते मौसम में लोग काफी लापरवाही बरतने लगते हैं। लोग ठंडा और पंखा का इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी टेंपरेचर वेरिएशन के कारण सर्दी खांसी और वायरल फीवर जैसी समस्याएं हो रही है। मौसम के उतार-चढ़ाव के समय लोगों को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए।'

IGIMS के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने बताया कि, 'बदलते मौसम में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर नियमित नहीं होने से ब्लड फ्लेक्चुएट होता है। इससे ब्रेन हेमरेज की समस्या काफी अधिक हो जाती है।'

IGIMS के कार्डियोलॉजी विभाग HOD डॉ. विष्णु देव प्रसाद ने बताया कि, 'इस मौसम में हृदयरोगियों को बेहद ही सावधानी बरतनी चाहिए। इस मौसम में ऐसे लोग खान-पान को लेकर सावधान रहें। पर्याप्त मात्रा में पानी पियें और फास्ट फूड से बचें। उन्हें इस मौसम में बेहद ही सतर्क रहना चाहिए।'

एलर्जी और खान-पान पर ध्यान देना जरूरी- फिजिशियन: IGIMS के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. भीम राम ने बताया कि, 'मौसम के उतार चढ़ाव के दौरान घर से बाहर निकलने से पहले बच्चे, बूढ़े और महिलाएं एलर्जी से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाकर निकलें। नियमित रूप से पानी का सेवन करें और खान-पान में विटामिन C युक्त संबंधित फलों का जरूर सेवन करें। अक्सर व्यायाम करने से पहले अपने शरीर अथवा रूम के टेंपरेचर को मेंटेन रखे।

शिशुओं का रखे बेहद ख्याल: पटना AIIMS के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. विनीत ने बताया कि, 'वायरल फीवर उन लोगों को अधिक प्रभावित करता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ऐसे में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कर प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना चाहिए।'

ख़ास ख़बर

पंचकूला : खाई में गिरी थार,एक की मौत व तीन घायल

लोकतंत्र की शान : चंडीगढ़। पंचकूला के मोरनी पर्यटक स्थल पर बुधवार सुबह थार गाड़ी के खाई में गिरने से हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। सभी युवक थार गाड़ी में सवार होकर घूमने निकले थे। यह हादसा मांधना गांव के पास हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार, थार गाड़ी स्पीड पर थी और संतुलन बिगड़ने के कारण खाई में गिर गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित करके खाई में गिरे युवकों को बाहर निकालकर अस्पतालपहुंचाया। हादसे का शिकार हुए सभी युवक 18 से 30 वर्ष की आयु के हैं। मृतक की पहचान सेक्टर-15, पंचकूला 21 वर्षीय अभिषेक खत्री के तौर पर हुई है।इसके अलावा पंचकूला के हरमिलाप नगर निवासी विवेक, मोहाली निवासी आयुष ठाकुर व ललित घायल हुए हैं। सभी युवक आपस में दोस्त हैं और वह आज मोरनी में घूमने के लिए निकले थे।

पानीपत: पुलिस मुठभेड़ में नाबालिग समेत तीन बदमाश काबू

लोकतंत्र की शान : पानीपत। पानीपत में बुधवार की अल सुबह हुई मुठभेड़ में पुलिस ने ट्रांसपोर्टर पर फायरिंग करने वाले तीन आरोपियों को काबू कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों घायल आरोपियों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। तीसरे नाबालिग बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईए वन प्रभारी इंस्पेटर फूलकुमार ने बताया कि बहुचर्चित ट्रांसपोर्टर सी. सुब्रमण्यम फायरिंग मामले में बुधवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस टीम ने इनके तीसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों घायल बदमाशों को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 24 जनवरी को इन बदमाशों ने महराणा गांव में ट्रांसपोर्टर को 3 गोलियां मारी थीं, जिनमें एक गोली सिर और दो पेट में लगी। घायल ट्रांसपोर्टर का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब पुलिस पता लगा रही है कि इन बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर पर हमला क्यों किया। प्रभारी के अनुसार पानीपत सीआईए वन और सोनीपत एसटीएफ की संयुक्त टीम को बदमाशों की गतिविधि की सूचना मिली थी। बुधवार अलसुबह जब पुलिस टीम ने गांव जौंर्धन खुर्द के रास्ते पर बदमाशों को घेरने की कोशिश की, तो खुद को फंसता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर फायरिंग की। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोलियां दो बदमाशों के पैरों में लगीं, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़े। मौके से भागते तीसरे बदमाश को भी पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया, मौके से कुल तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में काबू किए गए बदमाशों की पहचान गांव नौल्था निवासी सुनील, गांव डाहर निवासी प्रिंस व तीसरे की नाबालिग के रूप में हुई है। मुठभेड़ में आरोपी सुनील व प्रिंस के पैर में गोली लगी। दोनों घायल आरोपियों को पुलिस ने इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है।

गुरदासपुर में मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या

लोकतंत्र की शान : चंडीगढ़। पंजाब के गुरदासपुर में बुधवार की सुबह नकाबपोश युवकों ने मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। दुकान मालिक सामान्य की भांति दुकान खोल रहा था उसी समय युवकों ने उस पर फायरिंग कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद हमलावरों की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक डेरा बाबा नानक में बेदी मेडिकल स्टोर के मालिक रणबीर सिंह बेदी सुबह अपना मेडिकल स्टोर खोल रहे थे, उसी समय अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। रणबीर सिंह बेदी सिर में गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उन्हें अमृतसर रेफर किया गया, जहां जाते समय उनकी रास्ते मेंही मौत हो गई। रणबीर सिंह बेदी को पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थी। कुछ महीने पहले भी उन पर फिरौती को लेकर फायरिंग की गई थी। उनके मेडिकल स्टोर परपहले भी ऐसे ही हमले हो चुके हैं। पिछले साल भी यहां फायरिंग हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं। शहर की नाकाबंदी करके हमलावरों की तलाश की जा रही है।

चंडीगढ़ में पांच स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

लोकतंत्र की शान : चंडीगढ़। चंडीगढ़ में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब यहां के पांच स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। गणतंत्र दिवस की छुट्टियों के बाद आज सुबह ही स्कूल खुलेहैं । यह धमकी स्कूलों की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर दी गई है। स्कूलों में छुट्टी कर बच्चों को घर भेज दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वायड की मदद से सर्च की। जिन स्कूलों को धमकी दी गई है उनमें सेक्टर-25 स्थित चितकारा इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर-16 का मॉडल स्कूल, सेक्टर-45 का सेंट स्टीफन स्कूल, सेक्टर-35 का मॉडल स्कूल और सेक्टर-19 का मॉडल स्कूल शामिल हैं। पुलिस को इन स्कूलों में सर्च के दौरान कुछ नही मिला। सुरक्षा की दृष्टि से स्कूलों के आसपास पुलिस तैनात की गई हैं। चंडीगढ़ पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहुत जल्द इस बारे खुलासा किया जाएगा।

गोलीकांड के आरोपित ने किया थाने में आत्मसमर्पण

लोकतंत्र की शान : हरिद्वार। जमीनी विवाद को लेकर कनखल थाना क्षेत्र के ग्राम पंजनहेड़ी में हुए गोलीकांड के आरोपित ने कनखल थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है। जबकि घायलों का एम्स ऋषिकेश में उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कनखल क्षेत्र में ग्राम पंजनहेड़ी में हुए गोली कांड में सचिन और कृष्णपाल घायल हो गए थे। सचिन के एक तथा कृष्णपाल के तीन गोली लगी थी। सचिन के पेट में गोली लगने के कारण हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने सचिन को एम्स ऋषिकेश रैफर कर दिया। तरूण के भाई जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के मुताबिक अतुल चौधरी पुत्र सुखबीर, तरूण पुत्र दीपक, अभिषेक पुत्र सतबीर, गौरव पुत्र प्रदीप व अभिषेक पुत्र त्रिलोंक उषा टाउनशिप आए और उकसाने का काम किया। इसी दौरान कहासुनी में अतुल आदि ने फायरिंग शुरू कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। इसी बीच आरोपी अतुल चौहान कनखल थाने पहुंचा, जहां उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर पुलिस को सौंपते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और फायरिंग के पीछे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि दोनों गुटों के बीच चुनावी रंजिश चली आ रही थी। जिला पंचायत चुनाव में एक पक्ष को टिकट मिलने से दूसरा पक्ष नाराज था। वहीं भूमि विवाद भी इस झगड़े की वजह बना। पुलिस इस मामले में आगे की कार्यवाही कर रही है। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट जानकारी मिल सके। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

आज से शुरू होगा विंध्या अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

» इटली, मुंबई और तमिलनाडु से फिल्मकारों का सीधी आगमन शुरू

लोकतंत्र की शान, रामबिहारी पांडेय

सीधी। सिनेमा और संस्कृति के अनूठे संगम के रूप में पहचाना जाने वाला विंध्या अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल से सीधी ज़िले के वैष्णवी गार्डन में आरंभ होने जा रहा है। महोत्सव को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और देश–विदेश से आमंत्रित फिल्मकार, कलाकार व सिनेप्रेमी सीधी पहुंचने लगे हैं। महोत्सव का उद्घाटन समारोह कल प्रातः 11 बजे आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर, कामना पाठक, संदीप श्रीधर, महोत्सव संरक्षक इंजीनियर आर.बी. सिंह एवं डॉ. अनुप मिश्रा और महोत्सव के सहयोगी और शहर के गणमान्य लोग विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। फिल्म महोत्सव के निर्देशक प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि महोत्सव में भाग

लेने के लिए इटली, मुंबई तथा तमिलनाडु से आए फिल्मनिर्माताओं का सीधी आगमन शुरू हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय अतिथि के रूप में स्टेफानो रोसेटी (इटली), मुंबई से इंद्रमोहन सिंह एवं सतीश बादल, तमिलनाडु से संपत कुमार सुब्रमणियन एवं प्रभा के.ए., तथा भोपाल से अविनाश कुमार एवं आशीष बैठारी महोत्सव में शिरकत करेंगे। महोत्सव के सह-निर्देशक नीरज कुंदेर ने जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म महोत्सव के दौरान सिनेमा के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति और कारीगरी को भी विशेष स्थान दिया गया है। परिसर में मिट्टी और लकड़ी से बने हस्तशिल्प स्टॉल, विरासत महुआ आधारित खाद्य उत्पाद, तथा अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के सौंदर्य उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। विंध्या अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की विशेषता यह है कि यह एक दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, जहाँ सिनेमा के माध्यम से स्थानीय परंपराओं और वैश्विक सिने-दृष्टि के बीच संवाद स्थापित किया जाता है। उद्घाटन समारोह के पश्चात फिल्म स्क्रीनिंग की शुरुआत की जाएगी। महोत्सव के दौरान फिल्म प्रदर्शन, निर्देशक–अभिनेता संवाद, पैनल चर्चाएं, संगीत जामिंग नाइट एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार, यह महोत्सव न केवल सिनेमा को नए दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास है, बल्कि सीधी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सिने-मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी है।

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सफलतम आयोजन के लिये श्रवण शुक्ला सम्मानित

लोकतंत्र की शान , रामबिहारी पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख

सीधी। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित जिले के मुख्य कार्यक्रम में कलेक्टर श्री सोमवंशी के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में जिला शिक्षा विभाग से श्रवण कुमार शुक्ला जिला सांस्कृतिक प्रभारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि सीधी जिले में विगत माह पूजा पार्क के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को आयोजन 1 दिसंबर 2025 को सफलतम रूप से आयोजित किया गया था। जिसमें 1100 से ऊपर विद्यार्थी एवं कई सम्माननीय अतिथिगण उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम गीता के संदेश को जन.जन तक पहुंचाने का एक माध्यम था। इस सफलतम कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला शिक्षा अधिकारी की टीम ने कार्य किया जो अत्यंत सराहनी रहा। उक्त उपलब्धि पर गणतंत्र दिवस के दिन प्रमाण पत्र के साथ टीम को सम्मानित किया गया।

जिला मुख्यालय में चल रही भागवत कथा की पूर्णाहुति अवसर पर बोले व्यास

» भागवत कथा की अनुक्रमणिका श्रवण का अद्भुत फल

लोकतंत्र की शान, रामबिहारी पांडेय

सीधी। पूजापार्क सीधी में चल रही संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा के पूर्णाहुति दिवस में कथा व्यास बालाव्यंकटेश महराज वृन्दावनोपासक का भगतगणों ने माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत और व्यास पीठ की पूजा अर्चना सम्पन्न हुई। सन 2004 से अनवरत चलने वाली यह सार्वजनिक कथा के अध्यक्ष कुमुदिनी सिंह, संरक्षक सुरेन्द्र सिंह बोरा, सचिव डॉ श्रीनिवास शुक्ल सरस साहित्यकार, अंजनी सिंह सौरभ आदि पदाधिकारियों ने सभी पत्रकार साथियों के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किये तथा उपस्थित भक्तों हेतु धन्यवाद दिये। कथा श्रवण करने कई विशिष्ट जन पधारे उनमें से डॉ राजेश मिश्रा सांसद, रीती पाठक विधायक, सुरेन्द्र सिंह बन्ना मऊगंज, कमलेश्वर दिवेदी पूर्व मंत्री, कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री, दिलीप मिश्रा सतना, देवकुमार सिंह चौहान अध्यक्ष भाजपा, लालमणि सिंह पूर्व साडा अध्यक्ष, संतोश सिंह संविदाकार, के.के. तिवारी समाजसेवी, इन्द्रशरण सिंह चौहान पूर्व अध्यक्ष भाजपा, देवेन्द्र सिंह दादू, अजय प्रताप सिंह, देवेन्द्र सिंह मुन्नू पूर्व अध्यक्ष नपा, श्रीमती पूनम सोनी अध्यक्ष महिला भाजपा, भोला प्रसाद गुप्ता। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया, राजभान जी, बाबा मडरिया तथा दानबहादुर सिंह का नाम विशेष उल्लेखनीय रहा। कथा प्रसंग में व्यास जी ने कहा कि जिसने सात दिन तक कथा का श्रवण नही किया वह यदि अंतिम दिवस श्रीमद्भागवत की अनुक्रमणिका का श्रवण निष्ठा पूर्वक करले तो पूरे भागवत का फल प्राप्त होता है।व्यास जी ने भागवत कथा को आज के समय में कल्पतरु ज्ञापित करते हुए व्यास पीठ और भागवत महराज को नमन करके विश्राम किये। अंत में श्री कृष्ण रसामृत समिति के पदाधिकारियों ने भण्डारा एवं प्रसाद वितरण किया।

निजी अस्पताल का लोकार्पण करते हुए बोले धौहनी विधायक

» महानगरों की तर्ज पर जनपद स्तर पर मिलेगी चिकित्सा सुविधा

» मझौली मे श्री हास्पिटल का विधायक ने फीता काटकर किया शुभारंभ

लोकतंत्र की शान, रामबिहारी पांडेय ब्यूरो

सीधी। मझौली मे पुराने यूनियन बैंक के पास श्री हॉस्पिटल का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक कुवर सिंह टेकाम ने फीता काटकर किया शुभारंभ इस अवसर पर विधायक ने कहा कि चिकित्सा जगत में निरंतर अद्यतन तकनीक विकसित हो रही है। इस हास्पिटल के शुभारंभ हो जाने से मरीजों का इलाज नयी तकनीक के माध्यम से निश्चित रूप से संभव हो सकेगा। कहा कि भाजपा सरकार में सरकारी महकमें से लेकर प्राइवेट सेक्टर में विकास कार्य हो रहा है।वही श्री हॉस्पिटल के डायरेक्टर डा. विवेक सिंह ने बताया कि इस अस्पताल में ऑपरेशन अपेंडिक्स हाइड्रोसील हर्निया बवासीर गिल्टी गाव बच्चेदानी पथरी सिजेरियन नॉर्मल तथा बड़े ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है फार्मेसी पैथोलॉजी आईसीयू जनरल वार्ड प्राइवेट वार्ड ऑक्सीजन नेबुलाइजर इसीजी की सुविधा नगर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल सकेगी के मरीजों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आईसीयू की भी व्यवस्था इस हास्पिटल में सुलभ है। इस मौके पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष लवकेश सिंह, मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी, नगर परिषद अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता, उपाध्यक्ष उदयभान यादव जिला पंचायत सदस्य कृष्णलाल प्यासी, अखिलेश पांडे,, रामकुमार सिंह , मदन मोहन तिवारी, अजय सिंह छोटू, प्रदीप सिंह, रजनीश गुप्ता,, दो प्रवेश गुप्ता रमेश सिंह परिहार, अशोक सिंह, कमल पांडे, अमरनाथ सिंह, डॉ धीरेंद्र कुमार शर्मा, डॉ दिलीप कुमार सिंह, , डॉ सुनील कुमार, डॉक्टर शालिनी, नर्सिंग स्टाफ गीता ममता रेखा पंकज रितेश मीणा अंजलि निशा आदि लोग मौजूद थे।

देश भक्ति का रंग है भारत

लोकतंत्र की शान, राजेंद्र करनाल की रिपोर्ट

मन की उड़ान साहित्यिक संस्था करनाल द्वारा अपना बीसवां कार्यक्रम जिम खाना क्लब सैक्टर 8 करनाल में आयोजित किया। जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ कवि राजेन्द्र नाथ शर्मा ने की, मुख्य अतिथि डॉ. आसिमा गक्खड़ प्रिंसीपल दयाल सिंह कॉलेज करनाल रही, विशिष्ट अतिथि मदन लाल 'मधु' शिक्षक एवं हरियाणवी लेखक रहे। कार्यक्रम में देशभक्ति का रंग भरते हुए कार्यक्रम अध्यक्ष कवि राजेन्द्र नाथ शर्मा ने कहा विश्व गुरु बनेगा भारत, लहरें सात सुरों की सरगम,खुन पसीना बहा कर, लहराना है मां भारती का परचम, मुख्य अतिथि डॉ. आसिमा गक्खड़ ने अपने वक्तव्य में कहा हमारा देश एक गणतंत्र देश है जहां संविधान का प्राथमिकता के तौर पर पालन किया जाता है और जिससे देश की व्यवस्था निरन्तर निर्माण के साथ चलती हैं, संविधान ने सभी को बराबर के हक प्रदान किये हैं, जिससे देश ने तरक्की की है, विशिष्ट अतिथि मदन लाल मधु ने कहा जो कुछ मैंने या मुझ जैसों ने लिखा, दुनिया ऐसे ही चलती,अगर न भी लिखते, वरिष्ठ शायर इकबाल पानीपती ने देशभक्ति तराना पेश करते हुए कहा..आओ मिलकर बोलें बच्चे बूढ़े और जवान,के सारे जग से प्यारा अपना हिंदुस्तान, कवि दलीप खरेरा ने कहा परम् पर्व गणतंत्रता दिवस, मस्ती में झूमे हिन्दुस्तानी,गीत झांकियां भाषण कहते, भारत मां की गौरवमयी कहानी, वरिष्ठ शायर सिराज पैकर ने कहा मंदिर भी महफूज रहे, मस्जिद भी मिसमार ना हो, धर्मो मजहब के मुद्दों पर ,आपस में तकरार न हो, साहित्यकार डॉ महावीर प्रसाद शास्त्री ने कहा राज अंगरेजां का आया, छुप्प अन्धेरे घर म्हं समझों सांप लिकड आया, संस्था संस्थापक व युवा शायर रामेश्वर देव ने कहा संविधान से मिली तरक्की और मिला सम्मान है,हर इसां का हक है बराबर,ये इसकी पहचान है,संस्था अध्यक्ष पूनम गोयल ने कहा छोड़ न दे सफेद बालों की फ़िक्र, कोई तो होगा जो तुम्हारे माथे की बिन्दी पे मरता होगा,मधुर आवाज के धनी गुरमुख सिंह वड़ैच ने कहा तेरी खैरियत का जिक्र, रहता है दुआओं में, मसला सिर्फ मोहब्बत का नहीं, तेरे फ़िक्र का भी होता है, कवि राजकुमार मायूस ने कहा ऐ दिल ना उनके गम बढ़ा, उनके सामने जाकर नजर मिला, कवि नरेश लाभ ने कहा प्रेम घृणा से ऊपर होता,जग की है रीति,ऋतु बसंत आया उपवन में,कर लो उससे प्रीति, कवि डॉ आर बी कपूर ने कहा पास हांन एहम नहीं बस करीब होने की है, दौलत से गरीब होने से क्या बात दिल से गरीब होने की है, वरिष्ठ शायर हरबंस पथिक ने कहा पांव में रहते छाले हैं, फिर भी लब पे ताले हैं, कवयित्री डॉ हर्ष सेठी ने कहा एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया था,शायरा सुमन मुस्कान ने कहा ए वतन तुझको नमन करते हैं हम शान से, तेरे ही कारण है ऊंचा शीश सम्मान से,युवा शायर अशोक मलंग ने कहा ये आन हमारी है,ये शान हमारी है, कुर्बान तिरंगे पर, ये जान हमारी है, कवयित्री गुरविंदर कौर गुरी ने कहा कर्म पथ पर चलता राही,धुन अपनी में चलता चल, अशोक पाहवा ने कहा तेरी खुशियों के लिये ,सारे अरमान महोब्बत के दफना दूंगा, कवयित्री अनूजा कपूर ने कहा दिले नादान तुझे हुआ क्या है,बोल इस दर्द की दवा क्या है,युवा शायर कर्णजीत सिंह मान ने कहा किसे अपने बिछड़े वागूं,इक पीड मान नू खांदी ऐ,तेरे हिजर च सज्जना ने खाब वी कैदें आदें ने,, युवा शायर एल बी सीकरी ने कहा फकत दो चार ही सही यार बहुत हैं, इश्क- ए-नामुराद -ओ - सब्र -ए यार बहुत हैं, रमेश कुमार ने भी गीत से अपनी प्रस्तुति दी,रचनाकार राजन गांधी ने कहा सिर्फ मेरे चाहने से इश्क मुकम्मल कैसे होगा, कुछ तो चाहत इसमें तेरी भी हो। कार्यक्रम में कार्यक्रम अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिह्न व शाल भेंट कर सम्मानित किया गया, कार्यक्रम का मंच संचालन शायरा सुमन मुस्कान ने खुबसूरत अंदाज़ में किया। कार्यक्रम में रामस्वरूप राजेंद्र करनाल की रिपोर्ट जानबाज, गोपाल दास,देव , शीला रानी,कमल कुमार सहित श्रोताओं ने हिस्सा लिया।

मोदी सरकार के कशीदे पढ़ते हुए बोले चुरहट के पूर्व विधायक

» विकसित भारत की गारंटी है जी राम जी विधेयक

» चुरहट विधानसभा में जी राम जी योजना सम्मेलन आयोजित

लोकतंत्र की शान, रामबिहारी पांडेय ब्यूरो

सीधी । विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण विधायक 2025 के जन जागरण के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व चुरहट विधायक शरदेन्दु तिवारी के मुख्य आतिथ्य एवं भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में रामपुर नैकिन में संपन्न हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व चुरहट विधायक शरदेन्दु तिवारी ने कहा कि विकसित भारत बनाने की गारंटी है जी रामजी योजना। यह अधिनियम विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण विकास को गति देगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगी। रोजगार के दिन 100 से बढ़कर 125 दान कर दिया गया है। आजीविका और परिसंपत्ति निर्माण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। अध्यक्षीय उद्बोधन में भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने कहा कि यह विधेयक भ्रष्टाचार मुक्त एवं बहुआयामी है। इस विधेयक से ग्रामों का समग्र विकास होगा, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक होगा। विकसित भारत जी राम जी योजना से समस्त ग्राम पंचायत स्वावलंबी एवं सामर्थ्यवान होंगी। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक पटेल, अभियान टोली के संयोजक जिला उपाध्यक्ष शिवदान साकेत , नगर परिषद अध्यक्ष रामकुमार साहू, जिला मंत्री श्रीमती उर्मिला साकेत, अभियान टोली के सह संयोजक जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे, भानु पाण्डेय, युवा मोर्चा अध्यक्ष निशांत मिश्रा, मंडल अध्यक्ष विजय शंकर शुक्ला, प्रमोद सिंह, रजनीश शुक्ला, नीरज मिश्रा, विनोद पटेल, बुद्धिसेन साहू, हीरा सिंह, प्रदीप शुक्ला, महेन्द्र शुक्ला, कृष्णबहादुर सिंह, मुनिराज विश्वकर्मा, रवि साकेत, गुड़िया साकेत, नागेंद्र सिंह, नरेन्द्र सिंह, श्रीमती क्रांति निगम , पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच गण तथा जनप्रतिनिधि और मातृ शक्तियां उपस्थित रही।

समग्र शिक्षा अभियान सेकेण्डरी एजुकेशन की वार्षिक कार्य योजना निर्माण की बैठक आयोजित हुई

» मेरी शाला बेस्ट शाला का क्रियान्वयन समय सीमा में करें जिला शिक्षा अधिकारी ने बैठक में दिये निर्देश

लोकतंत्र की शान, रामबिहारी पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख

सीधी । कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशानुसार शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के प्राचार्यो को वार्षिक कार्य योजना की बैठक जिला शिक्षा अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह के मार्गदर्शन में शा.उ.मा.वि. क्रमांक-2 सीधी में सम्पन्न हुई। एपीसी रमसा डॉ सुजीत कुमार मिश्र द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना 2026-27 के सम्बंध में प्राचार्यो से विस्तार से चर्चा करते हुये आवश्यक शिक्षण कक्ष, लैब, बाउंड्रीवाल की आवश्यकता, शौचालय की जरूरत, पेयजल, विद्युतीकरण, वोकेशनल कोर्स, आई सी टी लैब से सम्बंधित आवश्यक जानकारी दी गई। बैठक में मेरी शाला बेस्ट शाला, 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम की कार्य योजना, परीक्षा पूर्व तैयारी, परीक्षा पे-चर्चा, कैरियर काउंसलिंग, एक्सपोजर विजिट, प्रेरणा उत्सव का पंजियन, भवन निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कराना, अधोसंरचना हेतु माग पत्र, स्पोकेन इंग्लिश की कोचिंग (परीक्षा उपरांत), दीक्षा पोर्टल, ई-विद्या, स्वच्छता साथी-वॉष आंन व्हील पर चर्चा हुई।जिला शिक्षा अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह ने सभी प्राचार्यो को निर्देशित किया कि 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम का लक्ष्य सभी स्कूल को प्राप्त करना है इसके लिये अतिरिक्त कक्षाये लगायें। कमजोर छात्रों को दूरभाष पर भी सहयोग करें। एडीपीसी श्री ओशो उत्सव ने प्राचार्यो को सभी मदो का खर्चा शीघ्र कराये जाने के निर्देश दियें। बैठक में आई टी सेल से देवेन्द्र तिवारी और जिले के सभी हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्य उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

जेल में अंधे हो सकते हैं इमरान खान, पूर्व पीएम को तुरंत इलाज की जरूरत, देर हुई तो रोशनी खो देंगे

इस्लामाबाद। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने गंभीर चेतावनी दी है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर कहा है कि अगर इमरान खान को तुरंत और सही इलाज नहीं मिला, तो उनकी एक आंख की रोशनी स्थायी रूप से जा सकती है और वे अंधे भी हो सकते हैं। PTI के मुताबिक इमरान खान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन (CRVO) नाम की बीमारी पाई गई है। जेल में डॉक्टरों की जांच में इस बीमारी को बेहद गंभीर और संवेदनशील बताया गया है। पार्टी ने कहा कि मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय में सही इलाज नहीं मिलने पर इमरान की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। पाकिस्तानी अखबार DAWN की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी का आरोप है कि मेडिकल सलाह के बावजूद रावलपिंडी की अडियाला जेल का प्रशासन इमरान खान का इलाज जेल के अंदर ही कराने पर अड़ा हुआ है। PTI ने डॉक्टरों के हवाले से कहा है कि इस बीमारी के इलाज के लिए ऑपरेशन थिएटर और विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है, जो अडियाला जेल में उपलब्ध नहीं हैं। पार्टी ने मांग की है कि इमरान खान को उनकी पसंद के किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। पार्टी ने विशेष तौर पर शौकत खानम अस्पताल या किसी अन्य अच्छे अस्पताल में इलाज कराने की बात कही है। साथ ही परिवार और करीबी लोगों से बिना रोक-टोक मिलने की अनुमति देने की मांग भी की गई है।

रूसी सैनिकों को कपड़े उतारकर पेड़ से बांधा, मुंह में बर्फ ठूंसी, यूक्रेन पर हमले से इनकार करने पर सजा

नई दिल्ली। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना करने वाले रूसी सैनिकों को उनके ही कमांडर बहुत बुरी तरह सजा दे रहे हैं। इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसे ही एक वीडियो में कुछ सैनिकों को कपड़े उतारकर ठंड में पेड़ों से बांध दिया गया। वे कड़ाके की ठंड में कांपते नजर आते हैं। एक वीडियो में एक सीनियर अधिकारी एक सैनिक के मुंह में जबरदस्ती बर्फ डालता है, जबकि सैनिक माफी मांगता है। अधिकारी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने आदेश नहीं माना और अपनी पोस्ट छोड़ने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सैनिकों ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से उन्हें यह सजा दी जा रही है। यूक्रेन के चैनल बुतुसोव प्लस ने इस हालात की तुलना जॉर्ज ऑरवेल की किताब एनिमल फार्म से की है और कहा है कि रूस में लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इसी बीच रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं, जबकि तापमान माइनस 20 डिग्री तक गिर गया है। हाल ही में हुए हमले के बाद खारकीव शहर के लगभग 80% हिस्से में बिजली नहीं है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि करीब 24 घंटे से बिजली नहीं है और बाहर माइनस 18 डिग्री की ठंड है। यूक्रेन अधिकारियों ने कहा है कि ऊर्जा व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है और उसे ठीक करने का काम चल रहा है।

ट्रम्प बोले- दूसरा नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा, नए समझौते पर सहमति का दबाव बनाया

वॉशिंगटन डीसी। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ शिकंजा और कसने की तैयारी में है। अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। एक भाषण में ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिका का एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि, इसकी उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान को नए समझौते पर सहमत किया जा सकता है। एक हफ्ते पहले भी ट्रम्प ने इसी तरह का बयान देते हुए कहा था कि एक बड़ा अमेरिकी सैन्य बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। बीबीसी फारसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी युद्धपोत 'USS अब्राहम लिंकन' मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। USS अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर-पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। ट्रम्प ने एक्सियोस को दिए एक अलग इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ स्थिति अभी बदल रही है। उन्होंने दावा किया कि ईरान अब बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। ट्रम्प ने कहा, 'ईरान के पास वेनेजुएला से बड़ा आर्मडा (बेड़ा) है।' उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के अधिकारी कई बार संपर्क कर चुके हैं और वे डील करना चाहते हैं। ट्रम्प का मानना है कि ईरान बात करने के लिए उत्सुक है।

मुंबई में फ्लाई ओवर 4-लेन से 2-लेन हुआ, सोशल मीडिया पर डिजाइन का मजाक बना

मुंबई। मुंबई के मीरा-भायंदर इलाके में मेट्रो लाइन-9 प्रोजेक्ट के तहत बने नए डबल डेकर फ्लाई ओवर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बना यह डबल-डेकर फ्लाई ओवर शुरुआत में फोर लेन का है लेकिन आगे चलकर अचानक सिर्फ टू लेन का रह जाता है। सोशल मीडिया पर इसकी डिजाइन को इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना बताते हुए तंज कसा जा रहा है। लोगों ने इसे 'डेथ ट्रैप' और 'आसमान में लगने वाला जाम' जैसे नाम दिए। लोगों ने कहा कि फोर लेन से अचानक टू लेन में सिमटने के कारण यह फ्लाई ओवर बोतलनेक साबित होगा, जिससे भारी ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने किसी भी तरह की डिजाइन खामी से इनकार किया। MMRDA के मुताबिक, फ्लाइओवर का यह लेआउट रोड ऑफ वे की सीमाओं और भविष्य की विस्तार योजना को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने X पर लिखा- महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग का चमत्कार। महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश BJP सरकार में ऐसे जानलेवा 'चमत्कार' आम हो चुके हैं। जनता परेशान हो या हादसों में जान गंवाए, सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। वहीं शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने लिखा कि इससे ट्रैफिक बढ़ेगा। डिजाइन को बेहतर बनाया जा सकता था।

जयपुर- एअर इंडिया की फ्लाइट रनवे टच कर फिर उड़ी, 10 मिनट बाद सफल लैंडिंग

जयपुर। दिल्ली से जयपुर पहुंची एअर इंडिया की फ्लाइट AI - 1719 की लैंडिंग फेल होने से दहशत फैल गई। बुधवार दोपहर को विमान रनवे को टच करते ही वापस उड़ गया। जानकारी के अनुसार फ्लाइट में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी थे। रंधावा पंजाब के पूर्व डिप्टी CM व गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद हैं। हालांकि करीब 10 मिनट बाद दूसरे प्रयास में विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले भी लैंडिंग फेल होने की घटनाएं सामने आई हैं। दरअसल, फ्लाइट AI - 1719 ने दोपहर करीब 1 बजकर 5 मिनट पर जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग का प्रयास किया था। इस दौरान पायलट ने रनवे को छूते ही विमान को दोबारा हवा में उठा लिया। एयरपोर्ट अप्रोच के कारण पायलट ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 'गो-अराउंड' का फैसला लिया। पहले प्रयास के बाद विमान ने एयरपोर्ट के ऊपर कुछ देर तक गोल चक्कर लगाया। करीब 10 मिनट बाद पायलट ने सफल लैंडिंग की। इस फ्लाइट में 135 पैसेंजर्स थे। सूत्रों के मुताबिक, इस फ्लाइट में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी सवार थे। घटना के दौरान विमान में मौजूद यात्रियों में कुछ समय के लिए चिंता जरूर रही। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि उड़ानों के संचालन में इस तरह की स्थिति पूरी तरह सुरक्षा मानकों के तहत आती है। ऐसे में पायलट को किसी भी स्तर पर लैंडिंग सुरक्षित नहीं लगती, तो वह विमान को दोबारा हवा में उठाने का निर्णय ले सकता है।

गाजा में अमेरिका के कारण हमारे सैनिक मरे: नेतन्याहू

एजेंसी, तेल अवीव

बाइडन पर हथियारों की सप्लाई रोकने का आरोप लगाया, कहा- अब अपनी हथियार इंडस्ट्री बनाएंगे

इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया है कि अमेरिका की वजह से इजराइल के कई सैनिक मारे गए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ गाजा जंग के दौरान हथियारों और गोला-बारूद की सप्लाई रोक दी गई थी। नेतन्याहू ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल के पास जरूरी गोला-बारूद खत्म हो गया था, इस वजह से कुछ सैनिकों की जान चली गई। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इस वजह से कितने सैनिकों की मौत हुई। इजराइली पीएम ने सीधे तौर पर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि यह स्थिति रोक तब खत्म हुई जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने। उनके मुताबिक, ट्रम्प के राष्ट्रपति बनते ही इजराइल को फिर से हथियार मिलने लगे। नेतन्याहू ने कहा कि विदेशी सैन्य सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए वे एक मजबूत और स्वतंत्र घरेलू हथियार इंडस्ट्री बनाएंगे।

अमेरिकी मदद पर निर्भरता कम करना चाहते हैं नेतन्याहू: नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध में सैनिकों की मौत आम बात है, लेकिन कुछ मौतों को टाला जा सकता था। गोला-बारूद की कमी के कारण सैनिकों को घरों में घुसकर लड़ना पड़ा और कई सैनिक मारे गए। लेकिन अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि अगले दशक के भीतर इजराइल अमेरिकी सहायता पर निर्भरता कम कर दे। उनका मकसद हथियार के क्षेत्र में ज्यादा स्वतंत्रता हासिल करना है, ताकि कभी भी हथियारों या गोला-बारूद की कमी न हो।

नेतन्याहू बोले- अब इजराइल के पास दो मकसद: नेतन्याहू ने कहा कि गाजा से आखिरी बंधक की वापसी के बाद अब इजराइल का पूरा ध्यान हमास से हथियार छीनने और गाजा को पूरी तरह से खाली करने पर है। उन्होंने कहा कि जब तक ये दोनों मकसद पूरे नहीं होते हैं तब तक गाजा में किसी तरह का पुनर्निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गाजा में डेवलपमेंट का काम पहले शुरू हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कई बार कह चुके हैं कि गाजा को दोबारा नए सिरे से रिस्ट्रक्चर और डेवलप किया जाना चाहिए, ताकि वहां से हिंसा और आतंकवाद की जड़ें खत्म हों।

नेतन्याहू बोले- अलग फिलिस्तीन किसी हाल में नहीं बनेगा: नेतन्याहू ने यह भी कहा कि एक अलग फिलिस्तीनी देश बनने की कोई संभावना नहीं है और न ही ऐसा होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक दोनों पर कंट्रोल बनाए रखेगा, भले ही बाकी देश एक अलग फिलिस्तीन को मान्यता देते रहें। नेतन्याहू ने कहा कि टू स्टेट सॉल्यूशन (द्वि राष्ट्र समाधान) को लागू होने से उन्होंने बार-बार रोका है। नेतन्याहू ने दोहराया कि इजराइल जॉर्डन नदी से लेकर समुद्र तक कंट्रोल बनाए रखेगा।

इराक में अपनी पसंद का पीएम चाहते हैं ट्रम्प

एजेंसी, बगदाद

कहा- नूरी-मलिकी को फिर प्रधानमंत्री बनाया तो कोई मदद नहीं करेंगे, उसकी नीतियां पागलों वाली

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि अगर इराक पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल-मलिकी को फिर से प्रधानमंत्री बनाता है, तो अमेरिका इराक से अपना समर्थन वापस ले लेगा। ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में लिखा, "मैं सुन रहा हूं कि महान देश इराक बहुत गलत फैसला ले सकता है और नूरी अल-मालिकी को फिर से प्रधानमंत्री बना सकता है।" उन्होंने कहा कि मलिकी के पिछले कार्यकाल में इराक गरीबी और हिंसा में डूब गया था। ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहिए। ट्रम्प ने आगे कहा कि मलिकी की नीतियां और विचारधारा पागलों वाली है। अगर वे चुने गए, तो अमेरिका इराक की मदद नहीं करेगा। बिना अमेरिकी सहायता के इराक के पास सफलता, समृद्धि या आजादी की कोई संभावना नहीं रहेगी।

मलिकी ने 2006 से 2014 तक इराक के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। माना जाता है कि उनके समय में ही इराक में सांप्रदायिक हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और ISIS जैसे उग्रवादी समूहों का उदय हुआ था। इससे पहले रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मौजूदा इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी से फोन पर बात की। रुबियो ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि अगली सरकार मिडिल ईस्ट में शांति लेकर आए। मलिकी ईरान के करीबी नेता हैं और ईरान के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते हैं। ट्रम्प ईरान को अपना बड़ा दुश्मन मानता है। उनको डर है कि मलिकी की वापसी से इराक में ईरान का प्रभाव और बढ़ जाएगा। इराक में संसदीय चुनाव 11 नवंबर 2025 को हो चुके हैं। यह इराक के 329 सदस्यों वाली संसद के लिए चुनाव था, जो राष्ट्रपति चुनती है और फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है।

हिमाचल में भारी बर्फबारी के बाद खिली धूप, भरमौर में ग्लेशियर गिरा

एजेंसी, शिमला

हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद आज अच्छी धूप खिली। इससे सड़क, बिजली व पानी की बहाली के काम में तेजी आई है। इससे पहले बीती रात में ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में अच्छी बारिश हुई। चंबा के भरमौर की पूलन पंचायत में बीती रात बड़ा ग्लेशियर गिरा। इसकी चपेट में दो पिकअप गाड़ी और तीन दुकानें आ गई। वहीं स्पीति में रात 10.30 बजे बर्फीला तूफान (स्नोस्टॉर्म) चला। चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू के दुर्गम क्षेत्रों में भारी हिमपात हुआ है। ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर को छोड़कर अन्य सभी 9 जिलों के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ गिरी है। मशहूर पर्यटन स्थल मनाली व भरमौर में 1.5 फुट ताजा फ्रेश स्नोफॉल हुआ।

रोहतांग दर्रा में 3 फुट, केलांग में 2, गोंदला में 1.5, कल्पा में 1.5 फुट, रिकांगपियो व कुफरी में 6 इंच, नारकंडा में 8 इंच, रिज पर 1 इंच और जाखू में 3 इंच बर्फ गिरी। इसके बाद चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति के सैकड़ों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है।

मनाली में बर्फ पर फिसली गाड़ी: बर्फबारी के बाद फिसलन के कारण सड़कें खतरनाक हो गई है। बीती रात को मनाली में एक कार 360 डिग्री में घूमी। अच्छी बात यह रही कि आगे कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी और सड़क सीधी थी। इससे गाड़ी रुक गई। इसे देखते टूरिस्ट समेत लोकल को भी सावधानी से बर्फ पर गाड़ी चलाने की एडवाइजरी दी गई है।

अमेरिकी अधिकारी बोले-ईयू से डील का भारत को ज्यादा फायदा, यूरोप के बाजार तक पहुंच मिलेगी

एजेंसी, वॉशिंगटन डीसी

टेलीग्राफ ने लिखा- मोदी व्यापार समझौते के असली विजेता

भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर अमेरिकी ट्रेड अधिकारी जैमीसन ग्रीर ने कहा है कि इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। उनके मुताबिक, यह डील कई मायनों में भारत के पक्ष में झुकी हुई है। ग्रीर ने फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि समझौते के लागू होने के बाद भारत को यूरोपीय बाजार में ज्यादा पहुंच मिलेगी और कुल मिलाकर भारत टॉप पर रहेगा। उन्होंने कहा, मैंने अब तक डील के कुछ डिटेल्स देखे हैं। ईमानदारी से कहूं तो इसमें भारत को फायदा मिलता दिख रहा है। भारत को यूरोप के बाजार में ज्यादा पहुंच मिल रही है। वहीं ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने भारत के लिए इस समझौते की तारीफ की है। अखबार ने लिखा है कि पीएम मोदी इस समझौते के असली विजेता है।

ग्रीर बोले- सख्त अमेरिकी ट्रेड नीति से EU नए बाजार ढूंढ रहा: ग्रीर ने यह भी कहा कि भारत-EU फ्री ट्रेड डील का एक बड़ा कारण अमेरिका की बदलती व्यापार नीति है। उनके मुताबिक, अमेरिका अब घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दे रहा है। साथ ही दूसरे देशों को अमेरिकी बाजार तक आसानी से पहुंच नहीं दे रहा। ग्रीर ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया और विदेशी देशों से आने वाले सामान पर शुल्क जैसे कदम उठाए गए। इससे कई देश, खासकर यूरोपीय यूनियन, अपने उत्पाद बेचने के लिए नए बाजार तलाशने लगे हैं। ग्रीर के मुताबिक, भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारतीय कामगारों की यूरोप में आवाजाही से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। उनका कहना है कि इस डील के तहत भारतीय प्रोफेशनल्स और वर्कर्स को यूरोपीय देशों में काम करने के ज्यादा मौके मिल सकते हैं। ग्रीर ने कहा ऐसा लगता है कि समझौते में कुछ इमिग्रेशन राइट्स भी दिए जा सकते हैं। मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन EU की राष्ट्रपति उर्सुला वॉन डर लेयेन पहले ही भारतीय वर्कर्स की यूरोप में मोबिलिटी की बात कर चुकी हैं। उनके मुताबिक, भारत इस ट्रेड डील से बड़े पैमाने पर फायदा उठाने वाला है। ग्रीर ने यह भी कहा कि इस समझौते से भारतीय कंपनियों को यूरोप में व्यापार बढ़ाने का बड़ा मौका मिलेगा।

ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने लिखा है कि यूरोपियन कमीशन FTA को अपनी बड़ी जीत बता रहा है, लेकिन हकीकत में इस समझौते के सबसे बड़े विजेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने जा रहे हैं। अखबार के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने इस समझौते के लिए भारत और रूस की करीबी दोस्ती को नजरअंदाज कर दिया है। पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नजदीकी जगजाहिर है, इसके बावजूद EU ने भारत से व्यापार बढ़ाने का रास्ता चुना।

यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट बोलीं-भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में टॉप पर पहुंचा

राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन डेलिगेट्स के लिए डिनर रखा गया, पीएम, सीजेआई शामिल हुए

एजेंसी, नई दिल्ली

यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन के सम्मान में मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में डिनर रखा गया। इस दौरान यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि भारत ग्लोबल राजनीति में टॉप पर पहुंच गया है। यह एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसका यूरोप स्वागत करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में, भारत-यूरोप की सोच और नजरिया एक जैसा है। हमारा मानना है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना सिर्फ सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है इस खास डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल समेत कई हस्तियां शामिल हुईं।

उर्सुला ने कहा: अगर यूरोप और भारत अपने संसाधनों और ताकत को मिलाएं, तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। इसी सोच के साथ आज दोनों साथ आए हैं। यह भारत-यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और साझेदारी का एक अहम मोड़ है। यह साझेदारी की शुरुआत भर है, आगे और बड़ा सहयोग होगा। भारत और यूरोप दुनिया को एक मजबूत संदेश दे रहे हैं। ऐसे समय में जब दुनिया में मतभेद और तनाव बढ़ रहे हैं, भारत और यूरोप बातचीत, सहयोग और तालमेल का रास्ता चुन रहे हैं।

इससे अस्थिर समय में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा। लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। कारोबार और निवेश को भरोसे और निश्चितता मिलेगी। इन समझौतों के साथ भारत और यूरोप और ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।

यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो बोले- आज के नतीजों पर गर्व: राष्ट्रपति भवन में हुए डिनर में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा- 'तेजी से बदलती दुनिया में, हमारी रणनीतिक साझेदारी बड़ा आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्व रखती है। मुझे आज के शिखर सम्मेलन के नतीजों पर गर्व है।' उन्होंने कहा कि यह एक सॉलिड डेवलपमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस पार्टनरशिप और 2030 के लिए जॉइंट स्ट्रैटजिक एजेंडा के साथ वैश्विक मुद्दों पर सहकारी नेतृत्व का एक उदाहरण पेश किया है।

इंदौर में दूषित पानी से 30वीं मौत हाईकोर्ट ने बनाया जांच आयोग

एजेंसी, इंदौर

इंदौर में दूषित पानी से बुधवार को 30वीं मौत हो गई। भागीरथपुरा में रहने वाले 62 वर्षीय लक्ष्मी रजक को दो दिन पहले उल्टी-दस्त की शिकायत हुई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था परिजनों ने बताया कि भर्ती के दौरान उनकी किडनी भी खराब होने की जानकारी मिली। इससे पहले भागीरथपुरा के खूबचंद की दूषित पानी से मंगलवार को मौत हो गई थी। बुधवार को उनके परिजनों ने अंत्येष्टि से पहले सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। हालांकि, अब भर्ती मरीजों की संख्या सिर्फ 6 रह गई है। इनमें से 3 आईसीयू में हैं। एक वेंटिलेटर पर है। दूसरी ओर इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मंगलवार (27 फरवरी) को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में ढाई घंटे से ज्यादा सुनवाई चली। शुरुआत में मुख्य सचिव अनुराग जैन 10 मिनट तक वर्चुअल उपस्थित रहे। इस दौरान 23 मौतों की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें से 16 मौतें दूषित पानी से मानी हैं, जबकि चार को लेकर असमंजस की स्थिति बताई है। वहीं तीन की मौत दूषित पानी से नहीं मानी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पेयजल का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। यह मामला गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति से जुड़ा है। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम की पेश रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर सुरक्षित पानी की सप्लाई, इलाज और जांच संबंधी निर्देशों का पूरा पालन नहीं हुआ है।

यूजीसी के नए नियमों का विरोध, यूपी में सवर्ण युवकों ने मुंडन कराया

एजेंसी, नई दिल्ली/लखनऊ/पटना

देशभर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों को लेकर विरोध जारी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की मांग स्वीकार की। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने वकीलों की दलीलों पर ध्यान दिया। सीजेआई ने कहा- हमें पता है कि क्या हो रहा है। सुनिश्चित करें कि खामियों को दूर किया जाए। हम इसे लिस्ट करेंगे। इधर, यूपी-बिहार में आज भी जमकर हंगामा हुआ। स्टूडेंट्स और सवर्ण जातियों के लोग सड़कों पर उतरे। यूपी के पीलीभीत में सवर्ण समाज के युवकों ने मुंडन कराया। बिहार में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर पर कालिख पोती गई।

UGC के नए नियमों का विरोध क्यों?: UGC ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका नाम है- 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026।' इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए हैं। ये टीमें खासतौर पर SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि सवर्ण छात्र 'स्वाभाविक अपराधी' बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी।

दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सिफारिश की थी: सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और

बिहार में फांसी मांगी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

उच्च शिक्षण संस्थानों में 'इक्विटी कमेटी' के गठन को अनिवार्य करने की सिफारिश संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति ने की थी। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह हैं। समिति में कुल 30 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सांसद शामिल हैं। इनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद शामिल हैं।

रोहित और डॉ. पायल का सुसाइड और SC का सख्त निर्देश: रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर थे। उन्होंने 17 जनवरी 2016 को सुसाइड किया। आरोप लगा कि रोहित दलित थे, इसलिए उनके साथ संस्थागत जातिगत भेदभाव हुआ। रोहित की मौत के बाद आत्महत्या के बाद देशव्यापी आंदोलन भी हुआ। जवाबदेही की मांग उठी। डॉ. पायल तड़वी मुंबई में मेडिकल की पोस्टग्रेजुएट छात्रा थीं। उन्होंने 2019 में सुसाइड किया। आरोप लगा कि आदिवासी समुदाय से होने के कारण पायल के सीनियर डॉक्टरों ने उनके साथ जातिगत भेदभाव किया था। लगातार उत्पीड़न के चलते पायल ने सुसाइड किया। हालांकि इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत आरोपी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। यह मामले सुप्रीम कोर्ट तक गया था। इनके अलावा भी अनिकेत अंभोरे मामला (AIIMS दिल्ली), सेंथिल कुमार मामला (JNU, 2008),अमन कचरू मामला (हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज, 2009) इनके अलावा अन्य मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के और भी जातिगत भेदभाव के मामले भी हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है।

यूजीसी के नए समानता विनियम 2026:- सामाजिक न्याय बनाम संवैधानिक संतुलन -एक समग्र, संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» यदि झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान नहीं जोड़ा गया, तो यह नियम सामाजिक न्याय के बजाय सामाजिक विभाजन का कारण बन सकते हैं?

» सामाजिक न्याय के नाम पर बनाए जाने वाले कानूनों नियमों में संविधान के अनुच्छेद 21 तथा 14 (समानता का अधिकार) और नेचुरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय) की मूल भावना का पालन करना जरूरी -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में दिनांक 28 जनवरी 2026 को संसद के बजट सत्र के प्रथम दिन माननीय राष्ट्रपति ने संसद के सभी सदनों को संबोधित करते हुए कहा 2014 की शुरुआत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल 25 करोड़ नागरिकों तक ही पहुंच पा रही थीं। मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से आज लगभग 95 करोड़ भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है,तो दूसरी ओर शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के लिए सवर्णो का आंदोलन छिड़ाहुआ है।हम जानते हैं कि वैश्विक स्तरपर भारत का उच्च शिक्षा तंत्र केवल ज्ञान का केंद्र नहीं है,बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों का संवाहक भीहै।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इस पूरे ढांचे का नियामक स्तंभ है,जिसके नियम देश के लाखों छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी द्वारा अधिसूचित और 15 जनवरी से प्रभावी किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम, 2026 इसी परंपरा का हिस्सा हैं। इन नियमों का घोषित उद्देश्य एससी,एसटी और अब पहली बार ओबीसी समुदायों के छात्रों व शिक्षकों को जातिगत भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करना है। उद्देश्य निस्संदेह संवैधानिक है,किंतु जिस प्रकार से दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं,मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि उन्होंने पूरे देश में गंभीर संवैधानिक, कानूनी और नैतिक बहस को जन्म दे दिया है।इन नियमों के लागू होते ही बिहार,उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश,राजस्थान सहित कई राज्यों में सवर्ण समाज के संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध का कारण आरक्षण नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया में असमानता और झूठी शिकायतों पर दंड के प्रावधान का पूर्ण अभाव है।आलोचकों का कहना है कि ये नियम सामाजिक न्याय के नाम पर संविधान के अनुच्छेद 21 तथा 14 (समानता का अधिकार) और नेचुरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय) की मूल भावना को कमजोर करते हैं। साथियों बात अगर हम यूजीसी का अधिकार क्षेत्र और उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी को समझने की करें तो यूजीसी जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहा जाता है,देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था का केंद्रीय नियामक निकाय है। 12वीं के बाद स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी या शोध, हर स्तर पर छात्र-छात्राएं किसी न किसी रूप में यूजीसी के नियमों के

अधीन आते हैं। यूजीसी का दायित्व केवल फंडिंग या मान्यता देना नहीं है,बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि शिक्षा प्रणाली संवैधानिक मूल्यों, न्याय, समानता और मानव गरिमा के अनुरूप संचालित हो।इसी दायित्व के तहत पहले एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून,आंतरिक शिकायत समितियां और समान अवसर केंद्र बनाए गए। अब 2026 के विनियमों में दो बड़े संशोधन किए गए हैं,पहला ओबीसी समुदाय को भी औपचारिक रूप से जातिगत भेदभाव के दायरे में शामिल किया गया है,यह एक ऐतिहासिक कदम है परंतु दूसरा झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी,यह इसके क्रियान्वयन में संतुलन की कमी गंभीर चिंता का विषय बन गई है। बस इसी बात पर सारे देश में स्वर्ण संगठन आंदोलन कर रहे हैं और हंगामा आगे और बढ़ाने की संभावना ज़ोरो से व्यक्ति के जारी है।

साथियों बात अगर हम इन संशोधनों को गहराई से समझने की करें तोपहला संशोधित प्रावधानःओबीसी को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल करना,यूजीसी द्वारा किया गया पहला बड़ा संशोधन यह है कि अब अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) के छात्र और शिक्षक भी उसी तरह जातिगत भेदभाव के संरक्षण दायरे में आ गए हैं,जैसे एससी और एसटी समुदाय पहले से थे। यह निर्णय सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओबीसी समुदाय की बड़ी आबादी आज भी शिक्षा संस्थानों में सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष भेदभाव का सामना करती है।हालांकि, आलोचना यह नहीं है कि ओबीसी को सुरक्षा क्यों दी गई, बल्कि यह है कि सुरक्षा का दायरा एकतरफा बना दिया गया है। यदि किसी सामान्य (जनरल कैटेगरी) वर्ग केछात्र या शिक्षक पर ओबीसी, एससी या एसटी से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया जाता है,तो उस पर कठोर संस्थागत प्रक्रिया शुरू हो जाती है जांच, निलंबन, प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक बदनामी,ये सभी उस व्यक्ति के जीवन को अपूरणीय क्षति पहुँचा सकते हैं।समस्या तब और गहरी हो जाती है जब अंततः शिकायत झूठी सिद्ध हो जाए। नियमों में ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। यह एकतरफा संरचना न केवल असंतुलित है, बल्कि संविधान की आत्मा के विरुद्ध भी है। दूसरा संशोधित प्रावधानः-झूठी शिकायतों पर दंड कापूर्ण अभाव,यूजीसी विनियम 2026 का दूसरा और सबसे विवादास्पद संशोधन यह है कि झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। पहले के नियमों और कई विश्वविद्यालयीय कोड ऑफ कंडक्ट में कम से कम अनुशासनात्मक कार्रवाई का विकल्प खुला रहता था। अब उसे पूरी तरह हटा दिया गया है। यह प्रावधान आलोचकों के अनुसार कानूनी दुरुपयोग को संस्थागत वैधता देता है। किसी भी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के खिलाफ यदि जातिगत भेदभाव का आरोप लगता है, तो वह दोषी सिद्ध होने से पहले ही सामाजिक रूप से अपराधी मान लिया जाता है। उसकी नौकरी, शोध, पदोन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लग जाता है। लेकिन यदि वर्षों बाद वह निर्दोष साबित होता है, तब भी न्याय अधूरा रह जाता है, क्योंकि जिसने झूठा आरोप लगाया, उस पर कोई जवाबदेही नहीं होती। साथियों बात अगर हम नेचुरल जस्टिस और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन इसको समझने की करें तो,भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। नेचुरल जस्टिस का मूल सिद्धांत है,कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दोषी नहीं ठहराया जाएगा और दोष सिद्ध होने पर ही दंड मिलेगा। यूजीसी के नए विनियम इन दोनों सिद्धांतों को कमजोर करते प्रतीत होते हैं।जब एक वर्ग को पूर्ण संरक्षण और दूसरे वर्ग को केवल दंड का सामना करना पड़े, तो यह समानता नहीं, बल्कि संरक्षित असमानता बन जाती है। न्यायपालिका ने भी कई फैसलों में कहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ प्रतिशोध नहीं, बल्कि संतुलन है। यदि झूठी शिकायतों पर कोई अंकुश नहीं होगा,तो यह व्यवस्था अंततः उसी सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुँचाएगी, जिसे बचाने के लिए यह नियम बनाए गएहैं। साथियों बात अगर हम संशोधन की स्थिति के बाद शिक्षा क्रे माहौल और सामाजिक ध्रुवीकरण को समझने की करें तो,इन संशोधित नियमों का सबसे बड़ा प्रभाव विश्वविद्यालय परिसरों के शैक्षणिक वातावरण पर पड़ेगा। शिक्षक और प्रशासक निर्णय लेने से डरेंगे, छात्र खुलकर संवाद करने से हिचकेंगे और हर असहमति को जातिगत चश्मे से देखा जाने लगेगा। इससे विश्वास का संकट पैदा होगा, जो किसी भी ज्ञान- आधारित संस्थान के लिए घातक है।साथ ही, सवर्ण और आरक्षित वर्गों के बीच पहले से मौजूद सामाजिक तनाव और गहरा हो सकता है। यदि न्याय एकतरफा प्रतीत होगा,तो प्रतिक्रिया भी सामाजिक स्तर पर असंतुलित होगी। यह स्थिति अंततः उसी सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कमजोर कर देगी, जिसके लिए ये नियम बनाए गए हैं। साथियों बात अगर हम यूजीसी समानता विनियम, 2026:- सुप्रीम कोर्ट में संभावित चुनौती क्रे संक्षिप्त ढांचे को समझने की करें तो (1)अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन, यूजीसी के नए विनियम जाति-आधारित भेदभाव की शिकायतों में एकतरफा संरक्षण प्रदान करते हैं। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के शिकायतकर्ताओं को पूर्ण सुरक्षा दी गई है, जबकि जनरल कैटेगरी के आरोपी व्यक्ति को समान कानूनी संरक्षण नहीं मिलता। झूठी शिकायत सिद्ध होने पर भी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक प्रावधान न होना, कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है।(2) नेचुरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय) का हनन,विनियमों में आरोपी के लिए प्रभावी सेफगार्ड्स का अभाव है। बिना प्रारंभिक जांच के कठोर संस्थागत कार्रवाई, तथा अंततः शिकायत झूठी पाए जाने पर भी शिकायतकर्ता की जवाबदेही न तय करना, (3) आधार केवल शिकायतकर्ता की जाति और आरोपी की सामाजिक श्रेणी है, न कि कृत्य की गंभीरता या प्रमाण। सुप्रीम कोर्ट के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, कोई भी वर्गीकरण,बुद्धिसंगत आधार और उद्देश्य से तार्किक संबंध पर खरा उतरना चाहिए। यह विनियम इस कसौटी पर विफल होते हैं। (4) न्यायिक समीक्षा से बचने का प्रयास,झूठी शिकायतों पर दंड हटाना संस्थागत दुरुपयोग को बढ़ावा देता है और न्यायिक हस्तक्षेप को अप्रभावी बनाता है। यह रूल ऑफ़ लॉ और डयू प्रोसेस की अवधारणा को कमजोर करता है।(5) अनुपातहीनता का सिद्धांत, भेदभाव रोकने के उद्देश्य से बनाए गए उपाय अत्यधिक कठोर हैं और कम दखल वाले विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें नहीं अपनाया गया। इससे अधिकारों पर अनावश्यक और अनुपातहीन प्रतिबंध लगता है। साथियों बात अगर हम इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के संदर्भ से समझने की करें तो यदि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें,तो संयुक्त राष्ट्र की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कोवनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दोनों ही यह स्पष्ट करते हैं कि न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष,संतुलित और जवाबदेह होनी चाहिए। किसी भी एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कानून में फ्रिवोलस या मैलिशियस शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा तंत्र मौजूद होता है। यूरोप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी नस्लीय या जातीय भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून हैं, लेकिन वहाँ झूठे आरोपों पर दंड का स्पष्ट प्रावधान होता है। भारत में यदि यूजीसी के नियम इस संतुलन को नहीं अपनाते, तो यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी सवाल खड़े कर सकता है कि क्या भारत का उच्च शिक्षा तंत्र निष्पक्षता के वैश्विक मानकों पर खरा उतरता है। अतः अगर हम अपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि यूजीसी के समानता विनियम, 2026 का उद्देश्य सही है,जातिगत भेदभावका अंत और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण लेकिन उद्देश्य की पवित्रता, साधनों की त्रुटियों को नहीं ढकसकती ओबीसी को सुरक्षा देना जरूरी है,लेकिन उसी के साथ न्यायिक संतुलन,उत्तरदायित्व और समानता भी उतनी हीआवश्यक है।यदि झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान नहीं जोड़ा गया, तो यह नियम सामाजिक न्याय के बजाय सामाजिक विभाजन का कारण बन सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 और नेचुरल जस्टिस केवल कानूनी शब्द नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा हैं। यूजीसी और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे इस आत्मा का सम्मान करें और नियमों में आवश्यक संशोधन कर न्याय को संतुलित, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाएं।

-संकलनकर्ता लेखक-
क्र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9284141425

अब स्मृतियां ही शेष : और मार्क टली जब भारत की आवाज बन गए

लेखक - ऋतुपर्ण दवे

एक जांबाज पत्रकार, वो शख्सियत जिसकी विश्वसनीयता ने भारत में विदेशी ब्रॉडकास्टर बीबीसी को वो पहचान दिलाई जो दुनिया में शायद ही किसी को मिली हो। यारों का यार होकर भी रिपोर्टिंग करते वक्त उसूलों से समझौता न करने वाली रिपोर्ट के धनी मार्क टली भारत में ही जन्मे भारत की मिट्टी में आखिरी सांस भी ली। फक गोरा होकर भी भारतीय परिवेश में रंगे टली जब फर्राटेदार कवरेज करते तो बरबस ही मुंह से निकलता ये गोरा कोई कैसा लंदन का। जीवन में जो सादगी, विनम्रता सहजता, संतुलन और सरलता उनमें बेमिशाल थी। दिखावे और ठाठ-बाट से दूर रहने वाले मार्क का जन्म 24 अक्टूबर 1935, टालीगंज, कोलकाता में हुआ और आखिरी सांस देश की राजधानी नई दिल्ली में 25 दिसंबर 2026 को ली। भारत को लेकर विदेशियों की राय भी प्रायः अलग-अलग रहती है। पत्रकार बिरादरी तो और भी अलग नजरिए से देखती है। भारत को कभी आध्यात्म तो कभी ऐसा देश समझते हैं जहां काफी कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन मार्क का नजरिया भारत के प्रति हमेशा से अलग रहा। उन्होंने न भारत को पर्यटन स्थल समझा और न ही विदेशियों की भांति उपनिवेशवादी मानसिकता से देखा। वो तो एक चलता, फिरता, हाड़मांस का पुतला बनकर भारत में रहे, जो दिखा वही लिखा और कहा। इसी विशेषता ने भारत में इतना भरोसेमंद और लोकप्रिय बना दिया कि एक समय आया और अभी भी है कि कहीं भीतर या मोहल्ले की गुप्त बातें भी साझा होती हैं तो कहा जाता कि बीबीसी लंदन की पक्की खबर है, गलत कैसे होगी! इतनी विश्वनीयता वह भी उस दौर में जब भारतीय मीडिया पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थी के बहुत कुछ मायने हैं। निश्चित रूप से मार्क टली के निधन से भारत ने अपना एक सच्चा दोस्त खो दिया है। मार्क टली के पिता एक रईस अंग्रेज थे जो व्यापारिक एजेंसी, गिलैंडर्स एंड अर्बुथनोट में वरिष्ठ भागीदार थे। ये तबकी बहुत बड़ी कंपनी थी जो कोयला खदानों, रेलवे और बीमा कंपनी का काम करती थी। उनकी मां का जन्म बांग्लादेश में हुआ था। बचपन के दस साल भारत में बिताया लेकिन भारतीयों से मिलने-जुलने की उन्हें आजादी नहीं थी। स्कूल शिक्षा खातिर उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा जहां ट्वाईफोर्ड स्कूल, मार्लबोरो कॉलेज और ट्रिनिटी हॉल तथा कैम्ब्रिज में पढ़े। धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। विचार पादरी बनने का था लेकिन दो सत्रों के बाद ही इसे बदला और 1964 में बीबीसी में शामिल हुए। 1960 के दशक में आकाशवाणी का बोलबाला था। मेल्विल डी मेलो जैसे बड़े नाम रेडियो पर राज करते थे। आकाशवाणी और रेडियो सीलोन का दबदबा था। ऐसे में रेडियो प्रसारण में जगह बनाना आसान नहीं था। लेकिन मार्क टली की निष्ठा, लगन थी जो कर दिखाया। तमाम कठिनाइयों, सरकारी दबाव के बावजूद 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1971 का मुक्ति युद्ध और बांग्लादेश का जन्म, 1975 का आपातकाल, 1980 के दशक का पंजाब विद्रोह और 5 जून, 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार कवर कर न केवल वो खास मुकाम बनाया बल्कि उन्हें इतिहास का प्रत्यक्ष गवाह बनने का मौका भी मिला। अन्य चर्चित कवरेजों में इंदिरा गांधी की हत्या, सिख विरोधी दंगे, राजीव गाँधी की हत्या एवं बाबरी मस्जिद विध्वंस भी रहे। आपातकाल में निष्पक्षता के चलते इन्दिरा गाँधी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थीं तो कुछ दिनों के लिए लंदन चले गए। 1975 के आपातकाल पर उनकी पुस्तक 'इंडियाज अनएंडिंग जर्नी' तो 1978 के प्रयागराज कुंभ का व्यापक कवरेज और उनकी पुस्तक 'नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया' पर इस सबसे बड़े मेले का पूरा वृतांत काफी चर्चाओं में रहा। मार्क टली को दक्षिण एशिया की पूरी जानकारी और समझ थी। इन देशों में व्यापक भ्रमण और कवरेज किया। जहां भी जाते केवल प्रशासनिक या राजनीतिक जानकारियां भर नहीं जुटाते बल्कि वहां के भू-भाग, सामाजिक ताने-बाने, संस्कृति, रीति-रिवाज भाषा, दाना-पानी, परंपरा और खान-पान से भी जुड़, समझ, उसे अनुभव करते। उनकी सादगी ने उन्हें एक अद्वितीय पत्रकार बनाया।

कौन करता है सरकारी भूमि पर कब्जा

- विवेक शुक्ला

देश के हरेक छोटे बड़े शहरों से लेकर महानगरों में सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर कब्जा जमाने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। जब कब्जा करने वालों को खदेड़ा जाता है, तब बवाल मच जाता है। दिल्ली ही नहीं, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में भी सार्वजनिक भूमि, फुटपाथ, पार्क और सड़कों पर अतिक्रमण आम हो गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, इन शहरों में हजारों एकड़ भूमि अवैध कब्जों से प्रभावित है, जिससे ट्रैफिक जाम, बाढ़ जैसी आपदाएं, पर्यावरण क्षरण और जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। उदाहरण के लिए, मुंबई में रेलवे भूमि पर 10,000 से अधिक अतिक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं, जबकि अन्य शहरों में फुटपाथ और सड़क किनारे पर दुकानें-ठेले सार्वजनिक स्थान को निगल रहे हैं। यह समस्या न केवल शहरी भीड़ बढ़ाती है, बल्कि बुनियादी ढांचे पर दबाव डालती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इस समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण जरूरी है। सबसे पहले, नियमित सर्वेक्षण और सख्त निगरानी प्रणाली होनी चाहिए। रेलवे और नगर निगमों को स्थानीय प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय करना होगा। अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की ठोस योजना बनानी होगी, ताकि कार्रवाई मानवीय हो। साथ ही, भूमि उपयोग नीतियों में सुधार, किफायती आवास योजनाओं का विस्तार और कानूनी प्रक्रिया को तेज करना आवश्यक है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अमित बंसल ने बीती 23 जनवरी 2026 को अपने एक अहम फैसले में दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया कि वह पूर्वी दिल्ली की मंडावली रोड पर अवैध ठेला वालों और अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बेशक, यह निर्देश एक मिसाल कायम कर सकता है और अन्य सड़कों तथा सरकारी सार्वजनिक भूमियों को अनधिकृत कब्जेदारों और भूमि माफिया से मुक्त कराने के लिए समान कार्रवाई को प्रोत्साहित कर सकता है।यह मामला स्थानीय निवासी जय चौधरी द्वारा दायर याचिका से शुरू हुआ, जिनकी ओर से अधिवक्ता उत्कर्ष सोनी ने पैरवी की। चौधरी की शिकायत में मुख्य रूप से सब्जी विक्रेताओं द्वारा सड़क के बड़े हिस्से पर कब्जा करने से होने वाली गंभीर असुविधाओं को उजागर किया गया था। याचिका के अनुसार, "लगभग 15 मीटर चौड़ी सड़क का करीब आधा हिस्सा आम लोगों के आवागमन (वाहन चलाने या पैदल चलने) के लिए खत्म हो गया है, और दिन में वाहनों की लोडिंग/अनलोडिंग से समस्या और बढ़ जाती है।" यह स्थिति दिल्ली में एक बड़ी बीमारी का रूप ले चुकी है, जहां सार्वजनिक मार्ग पर नियमित रूप से कब्जे हो जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम, सुरक्षा खतरे और निवासियों की जीवन गुणवत्ता में कमी आती है। इससे पहले, कोर्ट ने कई एजेंसियों को तलब किया था, जिनमें दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की स्पेशल टास्क फोर्स, और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस शामिल थे। इनसे प्रभावित क्षेत्र की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि " कोर्ट के फैसले का केवल डीडीए ने अनुपालन किया, जबकि अन्य ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की।" जस्टिस बंसल का नवीनतम आदेश अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ एक अहम फैसला है। "महानगरों में सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण की समस्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और विशेष रूप से रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जे आम हो गए हैं। यह समस्या न केवल शहरी विकास को बाधित कर रही है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात और बुनियादी ढांचे के विस्तार में भी बड़ी रुकावट बन रही है, यह बात दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सचिन पुरी कहते हैं। पिछले दिनों राजधानी के तुर्कमान गेट इलाके में कोर्ट ते आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए आए सरकारी मुलाजिमों और पुलिस से स्थानीय लोगों ने बहुत झगड़ा किया था। पुलिस ने बहुत से शरारती तत्वों को गिरफ्तार भी किया था। इस बीच. भारतीय रेलवे के पास देशभर में लगभग 4.99 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 1,068 हेक्टेयर से अधिक पर अतिक्रमण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में राज्यसभा में यह जानकारी दी थी। महानगरों में यह समस्या और गंभीर है, क्योंकि यहां जनसंख्या का दबाव अधिक है और भूमि की कीमत बहुत ऊंची है। मुंबई में रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गी-झोपड़ियां, दिल्ली में कई इलाकों में फुटपाथ और सड़क किनारे अतिक्रमण, कोलकाता और चेन्नई में भी इसी तरह के मामले सामने आते रहते हैं। हाल के वर्षों में गुवाहाटी, मोहाली, बांद्रा (मुंबई) जैसे स्थानों पर रेलवे ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए, जहां सैकड़ों संरचनाएं ध्वस्त की गईं। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण भी उतना ही चिंताजनक है। फुटपाथों पर दुकानें, ठेले, धार्मिक संरचनाएं या निजी वाहनों का पार्किंग होना आम बात हो गई है। दिल्ली की पॉश कॉलोनियों में भी फुटपाथ सिकुड़ते जा रहे हैं, जबकि गरीब इलाकों में अतिक्रमण हटाने के अभियान तेज हैं। इससे यातायात जाम, दुर्घटनाओं का खतरा और पैदल चलने वालों के लिए असुविधा बढ़ती है। इस समस्या के प्रमुख कारणों में तेज शहरीकरण, बेरोजगारी, गरीबी और भूमि की कमी शामिल हैं। प्रवासी मजदूर और निम्न आय वर्ग के लोग सस्ती जगह की तलाश में सरकारी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। सरकारी संपत्ति जनता की संपत्ति है। इसे बचाना और उसका उचित उपयोग सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। यदि महानगरों में अतिक्रमण पर प्रभावी रोक नहीं लगी, तो शहरी विकास और सार्वजनिक सुविधाओं का सपना अधूरा रह जाएगा। समय आ गया है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालें।

विवेक शुक्ला
9818155246

आरोपों से ऊपर उठे राजनीति के 'दादा-पुरुष'

लेखक- ललित गर्ग

यह खबर केवल एक व्यक्ति के निधन की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक पूरे युग के अचानक थम जाने की सूचना है। 28 जनवरी 2026 की सुबह जब बारामती में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार के असामयिक निधन की पुष्टि हुई, तो वह क्षण केवल पवार परिवार के लिए नहीं, बल्कि समूचे महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए गहरे शोक और स्तब्धता का कारण बन गया। जिस नेता को लोग अधिकार, अनुभव और निर्णय क्षमता का पर्याय मानते थे, उसका इस तरह अचानक चले जाना सत्ता, प्रशासन और राजनीतिक संतुलन में एक बड़ा रिक्त स्थान छोड़ गया है। एक संभावनाओं भरी महाराष्ट्र की राजनीति एवं राष्ट्रीय विचारों का सफर ठहर गया, उनका निधन न केवल महाराष्ट्र के लिये, भारत की राष्ट्रवादी सोच के लिये बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रवादी राजनीति पर एक गहरा आघात है, अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से सहकारी आन्दोलन को भी गहरा धक्का लगा है। अजित पवार का जीवन किसी राजसी विरासत की सहज कहानी नहीं था। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देओली प्रवरा क्षेत्र में जन्मे अजित पवार ने जीवन को बहुत करीब से संघर्ष करते हुए देखा। उनके पिता अनंतराव पवार फिल्म जगत से जुड़े रहे, राजकमल स्टूडियो में काम किया, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां साधारण रहीं। औपचारिक शिक्षा माध्यमिक स्तर तक ही सीमित रही, किंतु जीवन की व्यावहारिक पाठशाला ने उन्हें वह सिखाया जो बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थान भी नहीं सिखा पाते। शायद यही कारण रहा कि अजित पवार की राजनीति किताबों से नहीं, जमीन से निकली हुई राजनीति थी, जिसमें किसानों की पीड़ा, सहकारी संस्थाओं की ताकत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नब्ज साफ दिखाई देती थी। राजनीति में उनका प्रवेश किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि सहकारी आंदोलन की प्रयोगशाला से हुआ। 1982 में मात्र बीस वर्ष की आयु में उन्होंने एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव लड़ा। यह वही दौर था जब महाराष्ट्र की राजनीति में सहकारी संस्थाएं सत्ता की रीढ़ मानी जाती थीं। अजित पवार ने बहुत जल्दी समझ लिया कि यदि ग्रामीण महाराष्ट्र को साधना है तो उसे बैंक, चीनी मिल, सिंचाई और बिजली से जोड़ना होगा। यही समझ आगे चलकर उनकी राजनीतिक पहचान की सबसे बड़ी ताकत बनी। 1991 अजित पवार के राजनीतिक जीवन का निर्णायक वर्ष रहा। पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनने के साथ ही उन्होंने वित्तीय प्रशासन और संगठन संचालन में अपनी दक्षता का परिचय दिया। सोलह वर्षों तक इस पद पर बने रहना अपने आप में उनकी विश्वसनीयता और पकड़ को दर्शाता है। उसी वर्ष बारामती से लोकसभा के लिए निर्वाचित होना उनके बढ़ते कद का प्रमाण था, लेकिन उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। यह फैसला केवल पारिवारिक निष्ठा का नहीं, बल्कि राजनीतिक दूरदृष्टि का भी उदाहरण था। इसके बाद विधानसभा में प्रवेश और फिर लगातार बारामती से जीत ने उन्हें जनाधार का वह आधार दिया, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में विरले ही कोई चुनौती दे सका। अजित पवार को सत्ता के गलियारों में पहुंचाने वाली सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रशासनिक पकड़ थी। कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन जैसे कठिन और संवेदनशील विभागों को संभालते हुए उन्होंने विकास और विवाद दोनों को नजदीक से जिया। जल संसाधन मंत्री के रूप में कृष्णा घाटी और कोकण सिंचाई परियोजनाओं से उनका नाम जुड़ा। इन परियोजनाओं ने जहां किसानों के लिए पानी और उम्मीद का संदेश दिया, वहीं आलोचनाओं और आरोपों का बोझ भी उनके कंधों पर रखा। इसके बावजूद वे उन नेताओं में रहे जो फाइलों से नहीं, फैसलों से पहचाने जाते थे। उपमुख्यमंत्री के रूप में उनका सफर महाराष्ट्र की राजनीति में एक अनोखा अध्याय है। छह बार इस पद तक पहुंचना केवल राजनीतिक संयोग नहीं था, बल्कि सत्ता संतुलन, गठबंधन राजनीति और संगठनात्मक ताकत का परिणाम था। वे सरकार में अक्सर संकटमोचक की भूमिका में दिखे। बजट, वित्तीय प्रबंधन और संसदीय रणनीति में उनकी पकड़ ऐसी थी कि विरोधी भी उनके अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। उन्हें महत्वाकांक्षी कहा गया, कभी-कभी कठोर और रूखे स्वभाव का नेता भी बताया गया, लेकिन यह भी सच है कि सत्ता की वास्तविकता को वे भावनाओं से नहीं, निर्णयों से देखते थे। विवाद उनके राजनीतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे। सिंचाई घोटाले से लेकर बयानबाजी तक, कई मौके ऐसे आए जब उनकी छवि पर प्रश्नचिह्न लगे।

थाईलैंड मास्टर्स

अश्मिता चालिहा ने थाईलैंड मास्टर्स में बिखेरा जलवा

महिला एकल वर्ग के मुख्य ड्रॉ में पहुंचीं

नई दिल्ली, एजेंसी। अश्मिता चालिहा ने दो कड़े मुकाबले जीतकर थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 के महिला एकल मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। अब मुख्य ड्रॉ में उनका सामना साथी भारतीय खिलाड़ी देविका सिहाग से होगा। भारत की अश्मिता चालिहा ने दो कड़े मुकाबलों में जीत दर्ज कर थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल वर्ग के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश कर लिया। गुवाहाटी की 26 वर्षीय खिलाड़ी, जो सेलंगोर में आयोजित 2024 एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थीं, ने क्वालिफिकेशन के अपने पहले मुकाबले में चीनी ताइपे की हंग यी-टिंग को 42 मिनट चले मुकाबले में 21-15, 12-21, 21-12 से हराया।

इसके बाद अश्मिता ने कोरिया की किम जू यून की कड़ी चुनौती को पार करते हुए 45 मिनट में 21-11, 10-21, 21-16 से जीत हासिल की। मुख्य ड्रॉ में अश्मिता का सामना अब साथी भारतीय खिलाड़ी देविका सिहाग से होगा। अन्य मुकाबलों में, श्रेया लेले को क्वालीफिकेशन दौर में इंडोनेशिया की नी कादेक धिंदा अमर्त्या प्रतिवी से 12-21, 21-12, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा।

मिक्स्ड डबल्स क्वालिफिकेशन में एम जगलान और एल जगलान की जोड़ी को चीनी ताइपे के बो-युआन चेन और सुंग यी-शुआन ने एकतरफा मुकाबले में 21-12, 21-8 से पराजित किया।

अंडर-19 वर्ल्ड कप

लगातार चौथी जीत के बाद बोले भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे

इस खिलाड़ी की तारीफ की

बुलावायो (जिम्बाब्वे), एजेंसी। भारत ने आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे को हराकर लगातार चौथी जीत हासिल की है। मेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ 204 रन की जीत इस बात का सबूत है कि इस टीम में कितनी प्रतिभा है। ढ्ढष्टष्ट वेबसाइट के अनुसार वे सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन के कगार पर हैं, उन्होंने ड्ड, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत हासिल की है। लेकिन यह जीत इस टीम को वर्ल्ड कप के अहम पड़ाव के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद करती है; यह उनकी पहली जीत थी जो ष्ठरुस्-मेथड से प्रभावित नहीं हुई और यह पहली बार था जब उन्होंने पूरे 50 ओवर खेले जिसमें उन्होंने शानदार 352/8 रन बनाए, जो जिम्बाब्वे के लिए पीछा करने के लिए बहुत ज्यादा रन थे।

विहान मल्होत्रा प्लेयर ऑफ द मैच के लिए एक बेहतरीन पसंद थे, जिन्होंने 109* रन बनाए।

मेलबर्न, एजेंसी। जेसिका पेगुला ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में पेगुला ने अमांडा अनिसिमोवा को 6-2, 7-6(1) से हराया। दुनिया की नंबर 6 खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलियन ओपनः जेसिका पेगुला ने अमांडा अनिसिमोवा को हराकर

पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई

पेगुला ने 1 घंटे 35 मिनट तक चले क्वार्टरफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और दमदार जीत हासिल की। इस जीत से पेगुला अपने करियर में तीसरी बार और यूएस ओपन के बाहर पहली बार किसी मेजर ग्रैंड स्लैम के आखिरी चार में पहुंची हैं। सेमीफाइनल में पेगुला का मुकाबला एलेना रायबाकिना से होगा। इससे पहले पेगुला पिछले चार ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार चुकी थीं, लेकिन इस मैच में उन्होंने दोनों विंग्स से गहराई और सटीकता के साथ खेल को शुरू में ही कंट्रोल किया, और दो बार अनिसिमोवा की सर्विस तोड़कर पहला सेट अपने नाम किया। दूसरा सेट उतार-चढ़ाव वाला रहा। अनिसिमोवा ने अपना लेवल बढ़ाया, अपने आक्रामक बेसलाइन गेम पर ध्यान दिया, और पेगुला को आगे नहीं बढ़ने दिया। नंबर 4 सीड ने हिम्मत दिखाई, बराबरी पर रहीं, और मैच पॉइंट्स बचाकर सेट को टाईब्रेक में पहुंचा दिया, लेकिन एक बार वहां पहुंचने के बाद, पेगुला को कोई छू नहीं सका। पेगुला ने शुरू से ही ब्रेकर पर दबदबा बनाया, बिना डरे सर्विंग और तेज रिटर्न के दम पर लगातार सात पॉइंट्स बनाए। बढ़ते दबाव में अनिसिमोवा ने गलतियां कीं, जबकि पेगुला की रफ्तार और सटीकता निर्णायक साबित हुई।

इस जीत ने अनिसिमोवा के खिलाफ पेगुला का बिना हारे रिकॉर्ड 4-0 कर दिया। यह किसी अमेरिकी विरोधी के खिलाफ उनकी लगातार आठवीं ग्रैंड स्लैम जीत थी। जेसिका पेगुला तीन दशकों से ज्यादा समय में एक ही ऑस्ट्रेलियन ओपन में तीन हमवतन खिलाड़ियों को हराने वाली पहली अमेरिकी महिला भी बनीं, इससे पहले उन्होंने टूर्नामेंट में मैककार्टनी केसलर और डिफेंडिंग चैंपियन मैडिसन कीज को हराया था।

मैच के बाद जेसिका ने कहा, 'यह बहुत बढ़िया है। मैं पिछले कुछ सालों में यूएस ओपन के अलावा अन्य मेजर ग्रैंड स्लैम में आगे नहीं जा पाई थी। यह पहला स्लैम था जिसमें मैंने सच में कमाल कर दिया। मैं तीन बार, और फिर इस साल, चार बार क्वार्टर फाइनलिस्ट थी। मुझे यहां के हालात पसंद हैं। मैं यहां बहुत अच्छा टेनिस खेल पा रही हूं। इसलिए मैं सेमीफाइनल का इंतजार कर रही थी।

इगा स्वियाटेक बड़ी उलटफेर का शिकार

ऑस्ट्रेलियन ओपनः एलेना रायबाकिना से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुईं

मेलबर्न, एजेंसी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने दुनिया की नंबर-2 खिलाड़ी इगा स्वियाटेक को सीधे सेटों में 7-5, 6-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। रॉड लेवर एरिना में खेले गए इस मुकाबले में रायबाकिना की ताकतवर और सटीक गेम ने स्वियाटेक की करियर ग्रैंड स्लैम जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इगा स्वियाटेक और एलेना रायबाकिना के बीच ये मुकाबला 93 मिनट तक चला। दोनों ही अपने 12वें आमने-सामने के मैच में लय तलाशती दिखीं। शुरुआती गेम्स में सर्विस पर पकड़ ढीली रही और ब्रेक का सिलसिला चलता रहा। हालांकि निर्णायक मौकों पर रायबाकिना ने खुद को बेहतर तरीके से संभाला और पहले सेट में अहम बढ़त बनाते हुए 7-5 से अपने नाम किया। पहले सेट के बाद मुकाबले की दिशा पूरी तरह बदल गई। दूसरे सेट में रायबाकिना ने आक्रामक खेल दिखाया और स्वियाटेक को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने आखिरी नौ में से आठ गेम जीतकर मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया। इस जीत के साथ ही रायबाकिना ने स्वियाटेक के खिलाफ अपना आमने-सामने का रिकॉर्ड 6-6 से बराबर कर लिया। इस मैच में सर्विस का बड़ा रोल रहा। स्वियाटेक की पहली सर्विस केवल 49 प्रतिशत ही सफल रही, जिसका फायदा रायबाकिना ने लगातार उठाया। रायबाकिना ने पहले सेट में 0-40 की स्थिति से शानदार वापसी की और इसके बाद अपने अगले आठ सर्विस गेम में सिर्फ 12 अंक गंवाए।

रायबाकिना ने पिछले अक्टूबर से 19 में से 18 मुकाबले जीते हैं। यह उनकी लगातार आठवीं टॉप-10 खिलाड़ी के खिलाफ जीत है। 2022 विंबलडन चैंपियन रायबाकिना अब सेमीफाइनल में अमांडा अनिसिमोवा और जेसिका पेगुला के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता से भिड़ेंगी और अपने तीसरे करियर ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगी।

भारतीय टीम क्यों घर पर लगातार हार रही टेस्ट सीरीज

राहुल द्रविड़ ने खोले सारे राज, बताया कहां हो रही गड़बड़

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम अक्टूबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच दो टेस्ट सीरीज घर पर हार चुकी है. उसे न्यूजीलैंड ने 3-0 से मात दी तो साउथ अफ्रीका ने 2-0 से पीटा. इससे पहले 2012 से 2024 के बीच 12 साल तक भारत घर पर अजेय था.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और हेड कोच राहुल द्रविड़ ने पिछले दो साल से घर पर टेस्ट सीरीज गंवाने के पीछे क्या कारण हैं. उनका कहना है कि खिलाड़ियों का तीनों फॉर्मेट खेलना, लाल गेंद के क्रिकेट की तैयारी के लिए पर्याप्त समय न मिलना और नतीजे निकालने वाली पिचें इसके पीछे की वजह हो सकती हैं. भारत ने 2012 से 2024 के बीच घर पर कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई थी. लेकिन गौतम गंभीर के हेड कोच रहते अक्टूबर 2024 से नवंबर 2025 के दौरान 12 महीनों में दो सीरीज में घर पर हार मिली. पहले न्यूजीलैंड ने 3-0 से धूल चटाई. फिर साउथ अफ्रीका ने 2-0 से पीट दिया. भारत की घर पर टेस्ट में लगातार नाकामी पर द्रविड़ ने कुछ अहम बातें बताईं. उन्होंने 27 जनवरी को बेंगलुरु में एक इवेंट में कहा, 'एक कोच के रूप में जो बात मुझे समझ आई कि जो खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं वे एक फॉर्मेट से दूसरे में लगातार सक्रिय रहते हैं. ऐसा देखा गया है कि हमारे पास टेस्ट मैच से पहले तीन से चार दिन का समय रहता है और तब हम टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू करते हैं. फिर पलटकर देखने पर लगता है कि इन खिलाड़ियों ने इससे पहले आखिरी बार

चार या पांच महीने पहले लाल गेंद का सामना किया था. यह एक चुनौती है. टेस्ट मैच में स्पिन लेती पिच या सीम वाली पिच पर घंटों तक खेलना आसान नहीं होता है. इसके लिए काबिलियत चाहिए होती है.'

लगातार टूट रहा था टाटा का यह शेयर

अब आई तूफानी तेजी, 324 रुपये पर पहुंचा दाम

नई दिल्ली, एजेंसी। टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर लगातार लुढ़क रहे थे, कंपनी के शेयरों में अब तूफानी तेजी आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर बुधवार को ढ्ढस्श्व में 9 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 324 रुपये पर पहुंच गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में पिछले एक महीने में 28 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले 3 महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयर 40 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 75 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 77 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 27 जून 2024 को 1495.10 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 28 जनवरी 2026 को 324 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 61 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।

तेजस नेटवर्क्स को हुआ है 196 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा- टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 196.55 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड घाटा हुआ है। इस घाटे की मुख्य वजह कमजोर सेल्स रही है। एक साल पहले की समान अवधि में टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स को 165.67 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

निर्यात होगा दोगुना, लाखों नए रोजगार के अवसर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत -यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौता आधुनिक और नियम-आधारित व्यापार साझेदारी के रूप में तैयार किया है, जो मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच दोनों पक्षों को और करीब लाएगा। समझौते के लागू होने पर यूरोप से आने वाली लग्जरी कारें, चॉकलेट, शराब, वाइन, बिना तैयार हुए हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक सामान सस्ते होंगे।

समझौते के तहत भारत के 99 फीसदी से ज्यादा निर्यात को यूरोपीय संघ से जुड़े बाजारों पहुंच मिलेगी। वहीं, संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। भारतीय कारोबारियों खासकर छोटे और मझोले उद्यमियों (एमएसएमई) को लंबे समय के लिए स्थिर और भरोसेमंद बाजार मिलेगा। इससे वह यूरोप की आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बन सकेंगे और निवेश की बेहतर योजना बना पाएंगे।केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ÷इससे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बड़ा फायदा

होगा और मेक इन इंडिया को नई ताकत मिलेगी। देश में छोटे-मझोले उद्योगों को समझौते से व्यापक स्तर पर लाभ होगा। भविष्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी तेजी से पैदा होंगे।÷ बताया जा रहा है कि भारत को यूरोपीय बाजार में 97 फीसदी टैरिफ लाइनों पर प्राथमिकता मिलेगी, जो व्यापार मूल्य के हिसाब से 99.5 फीसदी है। समझौते के लागू होने पर करीब 70 फीसदी उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा, चमड़ा, जूते, चाय, कॉफी, मसाले, खिलौने, खेल का सामान, रत्न-आभूषण और समुद्री उत्पाद शामिल हैं।

कोटा सिस्टम के जरिए कम होगा कर- कुछ खास वस्तुओं पर कोटा सिस्टम के तहत कर कम किया जाएगा। इससे करीब 2.87 लाख करोड़ रुपये के ऐसे निर्यात को सीधा फायदा मिलेगा, जिन पर अभी यूरोप में चार से 26 फीसदी तक कर लगता है। भारत यूरोपीय संघ के 92 फीसदी से ज्यादा उत्पादों पर कर में राहत देगा, जिससे हाई-टेक मशीनरी और आधुनिक तकनीक भारत में सस्ती मिलेगी और उद्योगों की लागत घटेगी।

भारी-भरकम शुल्क घटाए जाएंगे- समझौते के तहत कई औद्योगिक उत्पादों पर भारी-भरकम शुल्क घटाए जाएंगे। जैसे कारों पर आयात 110 से घटाकर 10 फीसदी किया जाएगा (सीमित कोटा के साथ)। इससे वोक्सवैगन, ऑडी, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी यूरोपीय कारें भारतीय बाजार में सस्ती होंगी। मशीनरी, केमिकल्स और दवाइयों पर लगने वाले अधिकतर शुल्क पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। विमान, मेडिकल उपकरण, प्लास्टिक और स्टील जैसे क्षेत्रों को भी बड़ा फायदा मिलेगा।

50,000 उधार लेकर शुरू किया काम, भाई-बहन हुए फेल

गलती से ऐसा क्या सीखा कि अब 40,000 रोज की सेल

नई दिल्ली, एजेंसी। स्ट्रीट फूड का बिजनेस अक्सर सबसे आसान और कम रिस्क वाला माना जाता है। लेकिन, महाराष्ट्र के ठाणे में रहने वाले 23 साल के गणेश साठे की कहानी इसके बिल्कुल उलट है। उन्होंने साल 2023 में एक पुराने ठेले के साथ अपने बेन्ने डोसा के सफर की शुरुआत की थी। यह शुरुआती दौर में भारी नुकसान और मानसिक तनाव का कारण बना। बहन सपना साठे के साथ मिलकर उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा। बेंगलुरु के डोसा कल्चर को समझा। रतन टाटा के विचारों से प्रेरणा ली। अक्टूबर 2025 में नए सिरे से लॉन्च हुए द बेन्ने ने आज रोजाना 40,000 रुपये की बिक्री का आंकड़ा छू लिया है। यह एक छोटी सी शुरुआत की बड़ी जीत को दर्शाता है। आइए, यहां गणेश साठे की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं।

पहली शुरुआत में बड़ा फेलियर- गणेश साठे सीए की पढ़ाई कर रहे थे। हमेशा से वह खुद का कुछ करना चाहते थे। जनवरी 2023 में उन्होंने माता-पिता से 50,000 रुपये उधार लेकर घर के पुराने ठेले पर अपनी मां के हाथ के स्वादिष्ट बेन्ने डोसा बेचना शुरू किया। लेकिन, बाजार की प्रतिस्पर्धा, खराब लाइटिंग वाले ठेले और बारिश के मौसम ने उनके हौसले तोड़ दिए। जहां वीकेंड में 3,000 रुपये की कमाई होती थी, वह गिरकर 200 रुपये पर आ गई। भारी नुकसान

के कारण 2024 के मध्य में एक समय ऐसा आया जब गणेश टूट गए और उन्होंने रोते हुए काम बंद करने का फैसला कर लिया। बेन्ने डोसा कर्नाटक के दावणगेरे की प्रसिद्ध डिश है। इसमें बेन्ने का मतलब मक्खन होता है। इसे भारी मात्रा में शुद्ध सफेद मक्खन के साथ तैयार किया जाता है।

ऐसे हुआ गलतियों का एहसास- हार मानकर घर बैठे गणेश और उनकी बहन सपना को नई दिशा तब मिली जब वे बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे गए। वहां के डोसा कल्चर को देखकर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने नए सिरे से शुरुआत करने की ठानी। इसी दौरान रतन टाटा की एक पोस्ट ने गणेश में नई ऊर्जा भर दी। इसके बाद उन्होंने अपने ठेले पर रतन टाटा से प्रेरित लिखवाया। उन्होंने अपनी मां को फिर से राजी किया और 30,000 रुपये के छोटे से ऑनलाइन लोन और मां की मदद से अपने ठेले को एक नया और प्रीमियम लुक दिया।

ठेले से पक्की दुकान तक का सफर- नगर निगम की चुनौतियों और बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब गणेश और सपना ने अपने व्यवसाय को स्थाई बनाने का फैसला लिया है। ग्राहकों को डोसे के लिए 20-30 मिनट का इंतजार न करना पड़े, इसलिए उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई और माता-पिता के सहयोग से ठाणे में ही एक पक्की दुकान सुरक्षित कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि यह दुकान उसी स्थान पर है जहां उन्होंने 2023 में पहली बार अपना ठेला लगाया था। इंस्टाग्राम पर 5,000 से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ ये युवा उद्यमी अब अपनी फिक्स्ड डोसा शॉप की हर छोटी-बड़ी तैयारी को दुनिया के साथ साझा कर रहे हैं।

दोबारा लॉन्चिंग पर जोरदार सफलता

अक्टूबर 2025 में द बेन्ने को आधिकारिक तौर पर फिर से लॉन्च किया गया। इस बार गणेश और सपना ने अपनी पूरी तैयारी और संघर्ष की कहानी इंस्टाग्राम पर शेयर की। इससे उन्हें जबरदस्त स्थानीय प्रसिद्धि मिली। देखते ही देखते ग्राहकों की संख्या 20 से बढ़कर रोजाना 300-400 तक पहुंच गई। महज ढाई घंटे के ऑपरेशन में उनका सारा स्टॉक बिकने लगा। उनकी डेली सेल यानी दैनिक बिक्री 40,000 रुपये तक पहुंच गई। शुद्ध सामग्री और पुणे से मंगाए गए सफेद मक्खन के स्वाद ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया।

कॉपर की कीमतों में उछाल, एसी-फ्रिज हो गए महंगे

लोगों को नहीं मिल रहा जीएसटी रिफॉर्म का फायदा

नई दिल्ली, एजेंसी। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बुरी खबर है। कॉपर (तांबा) की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर अब सीधे बाजार में दिखने लगा है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हर हफ्ते कीमतों में बदलाव हो रहा है। इससे कारोबारियों की टेंशन बढ़ गई है दावा है कि जनवरी में ही एसी, फ्रिज समेत कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम के दाम में

तेजी आ चुकी है। साथ ही आने वाले दिनों में कॉपर से बने हर आइटम की कीमत में करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी बढ़ती महंगाई की वजह से जीएसटी रिफॉर्म का फायदा लोगों को नहीं मिल सकेगा। जानकारी के मुताबिक, एसी, फ्रिज, पंखे समेत कई ऐसे आइटम हैं, जिनका इस्तेमाल हर घर में होता है। पिछले साल केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म का तोहफा दिया था, जिससे कार से लेकर एसी टीवी समेत कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कीमतों में गिरावट आई है। लोगों ने सरकार की इस पहल की जमकर तारीफ भी की लेकिन अब यह राहत मिलना मुश्किल हो जाएगा। यह कहना है कि कमला नगर मार्केट के इलेक्ट्रॉनिक आइटम के कारोबारी विकास तनेजा का।

कितनी बढ़ गई कीमत- उन्होंने बताया कि बीते दो महीने में कॉपर के रेट में करीब 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है यानी एक हजार रुपये प्रति किलो मिलने वाला कॉपर अब लगभग 1400 रुपये का हो गया है। इसका असर अब बाजार पर पड़ने लगा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)